[2017] 9 एस. सी. आर 212

आरई में, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

(2017 की स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 1)

9 मई, 2017 1 और 4 जुलाई, 2017 2

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई, दीपक मिश्रा,

जे. चेलामेश्वर, रंजन गोगोई,

मदन बी. लोकुर, पिनाकी चंद्र गौस और

कुरियन जोसेफ, जे. जे.]

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971। 2 (ख), 2 (ग)-- न्यायालय की अवमानना-उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही

- एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा आपराधिक, अवमानना की कथित कार्रवाई-न्यायमूर्ति के

- उन्होंने असंख्य न्यायाधीशों के खिलाफ अप्रिय आरोप लगाए

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन ज्यादातर इसके खिलाफ

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-मीडिया को संबोधित करते हुए पत्र लिखे,

उच्चतम संवैधानिक अधिकारियों को संबोधित पत्राचार;

और 1989 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

अधिनियम-न्यायमूर्ति के द्वारा पारित स्वतः संज्ञान न्यायिक आदेश, इसके बाद भी

अवमानना नोटिस जारी करना-आयोजितः न्याय की कार्रवाई 'के' का गठन किया गया

न्यायालय की अवमानना की सबसे बड़ी और गंभीर कार्रवाई-वह भी अदालत के सामने अवमानना की-कोई भी आरोप नहीं

न्यायमूर्ति 'के' द्वारा लगाए गए आरोप किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित थे-उनका

आरोप दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक थे, और स्पष्ट रूप से नाम से,

कई संबंधित न्यायाधीशों के खिलाफ-उन्होंने अपने आरोप लगाए बड़े पैमाने पर जनता को पत्रों के माध्यम से, और इंटरनेट के माध्यम से-उनके कुछ

राष्ट्रपति को लिखे गए पत्रों का जानबूझकर समर्थन किया गया था

तमिलनाडु अधिवक्ता संघ-के दौरान

तत्काल अवमानना याचिका की सुनवाई, सर्वोच्च न्यायालय का उनका उपहास

अदालत बेरोकटोक रही-उन्होंने इसके द्वारा पारित आदेशों पर भी रोक लगा दी।

न्यायालय और इस पीठ के न्यायाधीशों को भी जाने से रोक दिया।

देश ने उन्हें दोषी ठहराया और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई

इस प्रकार कारावास, दंडनीय, उसकी अप्रियता के लिए

(पर खेहर, सीजेआई) ' जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई, दीपक मिश्रा, जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी. लोकुर, पिनाकी चंद्र घोष और कुरियन जोसेफ, जे. जे. की पीठ ने फैसला सुनाया। * जे. चेलमेश्वर और रंजन गोगोई, जे. जे. की पीठ द्वारा निर्णय।

212 आरई में, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

अदालत की अवमानना-उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-न्यायाधीश द्वारा लगाए गए अप्रिय आरोप

बड़ी संख्या में नामित न्यायाधीशों और न्यायपालिका की ओर-आयोजितः संबंधित लोगों की छवि को गंभीर रूप से धूमिल किया है, और

समग्र रूप से न्यायपालिका-इस प्रकार, अदालत की अवमानना के लिए स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू करना। (पर खेहर, सीजेआई)

द्वारा भ्रष्टाचार और विभिन्न अपराधों के आरोप। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उत्तरवर्ती मुख्य न्यायाधीश। न्यायालय-संवैधानिक अधिकारियों को संबोधित पत्र-न्यायाधीश 'के'

उक्त न्यायाधीशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को आदेश देते हुए आदेश पारित किया-आरोपों को सार्वजनिक किया गया,

न्यायपालिका की विश्वसनीयता-न्यायाधीश के खिलाफ स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही-न्यायाधीश का मामला कि कोई अवमानना कार्यवाही नहीं हो सकती है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ शुरू किया गया; कि न्यायाधीश के खिलाफ केवल कानूनी कार्रवाई उन्हें महाभियोग द्वारा पद से हटाना था और उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करना होगा।

यह 1989 के अधिनियम के तहत एक अपराध हैः अदालत ने कहा है

अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अधिकार क्षेत्र-इस न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू की गई वर्तमान अवमानना कार्यवाही से इसकी स्थिरता पर कोई फर्क नहीं पड़ता-न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है हमेशा कुछ उच्च न्यायालयों में अंतर्निहित होने के लिए मान्यता दी गई है-अदालत को बदनाम करना और किसी भी न्यायिक कार्यवाही के नियत पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करना अवमानना का गठन करने वाला कार्य माना जाता है।

न्यायालय का-न्यायालय के विचाराधीनता के दौरान अवमानकर्ता का आचरण

इस न्यायालय में कार्यवाही निश्चित रूप से आपराधिक अवमानना का गठन करती है-मुख्य कार्यवाही न्यायपालिका को बदनाम करने के अवमानक के अपराध का पता लगाने में समाप्त हो सकती है या नहीं भी हो सकती है।

इसके बजाय, उन्होंने उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ अवमानना के आरोप की जांच करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने का फैसला किया और अवमानना करने वाले के कार्यों ने न्यायिक प्रणाली को बदनाम किया और इसकी क्षमता है व्यवस्था में औसत नागरिक के विश्वास को हिलाना-थोड़ा सा भी पछतावा न दिखाना एक शमन कारक हो सकता है-इस तरह का आचरण और कार्य, यदि सहन किया जाता है, तो निश्चित रूप से व्यवस्था में कमजोरी के तत्व को दर्शाता है-अवमानना के लिए समकालीन को दंडित किया जाएगा ए

आई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[201

7] 9 एस सी आर।

भारत का संविधान-कला। 124 (4) और 217 (1) (बी)-अनुसूचित

-

जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।

(प्रति चेलमेश्वर, जे.)

न्यायपालिका-संवैधानिक अदालतें-प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है

संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति

- स्थितियों से निपटने के लिए उचित कानूनी व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है

जहाँ किसी संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण की आवश्यकता होती है

महाभियोग के अलावा सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। (प्रति।

चेलमेश्वर, जे.)

याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः (क्यूरियम के अनुसार)

1.1 . न्यायमूर्ति 'के' के कार्यों ने सबसे अधिक और

न्यायालय की अवमानना की गंभीरतम कार्रवाई। उन्होंने वचन भी दिया है।

अवमानना, न्यायालय के सामने। इसलिए वह उत्तरदायी है

उसके अप्रिय कार्यों और व्यवहार के लिए दंडित किया गया। उसे होना चाहिए।

छह महीने के कारावास के साथ उसके कार्यों के लिए दंडित किया गया। [पैरा

36] [262 - डी]

1.2 समय-समय पर न्यायमूर्ति 'के' द्वारा लिखे गए पत्रों का पाठ

समय-समय पर, स्वतः संज्ञान प्रक्रिया की भी जांच की गई है

उनके द्वारा अपनाया गया, जिसके तहत उन्होंने ऐसे आदेश पारित किए जो अपमानजनक थे

न्याय प्रशासन के लिए, इससे पहले कि उसे नोटिस जारी किया गया था अवमानना, इस न्यायालय द्वारा। न्यायमूर्ति 'के * सुओ द्वारा पारित आदेश

मोटु (उस में निहित अधिकार क्षेत्र के कथित प्रयोग में)

0

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, धारा के साथ पढ़ा गया

482 दंड प्रक्रिया संहिता), जारी होने के बाद भी

इस न्यायालय द्वारा उन्हें दिए गए अवमानना नोटिस का विश्लेषण किया गया है।

उसका व्यवहार और अधिक आक्रामक हो गया था,

इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में समय-समय पर आदेश पारित किए।

उनके द्वारा संबोधित पत्रों की सामग्री में शामिल थे

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध निंदनीय सामग्री और सुप्रीम कोर्ट। इस पत्राचार को संबोधित किया गया था

सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण, तीनों शाखाओं में

शासन-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बिनि।

सार्वजनिक बयानों ने न्यायिक प्रणाली को हंसी के पात्र में बदल दिया।

स्थानीय मीडिया, इससे होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना

न्यायिक संस्थान ने खुशी-खुशी 'के' लहर की सवारी की। यहाँ तक कि विदेशी भी

मीडिया ने भारतीय न्यायपालिका पर कटाक्ष किया था।

उनका कोई भी कार्य माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन द्वारा नहीं किया जा सकता है।

प्रामाणिक माना जाए, विशेष रूप से एक्सप्रेस को देखते हुए

इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों में उनसे बचने की आवश्यकता है -

किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक कार्य का निर्वहन। उसे रोकने के लिए स्वतः संज्ञान अधिकारिता का दुरुपयोग करते हुए, इस न्यायालय द्वारा एक और आदेश पारित किया जाना था जिसमें न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, आयोगों और अधिकारियों को न्यायमूर्ति द्वारा पारित किसी भी आदेश का संज्ञान लेने से रोका गया था।

' के '{पैरा 33] [259-सी-जी]

1.3 जस्टिस 'के' ने रणशिंग बजाकर खुद को कार्यों से बचाया

एक कम विशेषाधिकार प्राप्त जाति से संबंधित होने के रूप में उनकी स्थिति। उक्त पद ग्रहण करके उन्होंने अप्रिय आरोप लगाए उच्चतम न्यायालय के असंख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ, लेकिन ज्यादातर मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ। लगाए गए किसी भी आरोप का समर्थन नहीं किया गया था

कोई भी सामग्री। उनके आरोप दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक थे, और

स्पष्ट रूप से नाम से, कई संबंधित न्यायाधीशों के खिलाफ। वह. अपने आक्षेपों को बड़े पैमाने पर जनता के सामने लाया, पहली बार में,

उनके पत्रों का सावधानीपूर्वक समर्थन करके ताकि उनके संचार की सामग्री को वांछित हलकों में व्यापक रूप से प्रसारित किया जा सके। इनमें से कुछ

तमिलनाडु अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को उनके पत्रों का जानबूझकर समर्थन किया गया था। और बाद में, इंटरनेट के माध्यम से, उन्होंने अपने दृष्टिकोण और पूरी सामग्री को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा। तत्काल अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय का उनका उपहास बेरोकटोक जारी रहा। वास्तव में, यह ऊँचा था, जैसा पहले कभी नहीं था। इस प्रक्रिया में, उन्होंने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर भी रोक लगा दी। उनके द्वारा पारित आदेशों से उन्होंने इस पीठ के न्यायाधीशों को देश छोड़ने से रोक दिया, उन्होंने इस पीठ के न्यायाधीशों को दोषी ठहराया और उन्हें 5 साल के कारावास की सजा सुनाई।

दोषी ठहराए गए न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत खर्च। स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए, इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि न्यायमूर्ति 'के' द्वारा जारी किए गए किसी भी बयान को आगे प्रचारित नहीं किया जाएगा। हालाँकि, तत्काल प्रतिबंध आदेश न तो रोकता है और न ही बाधा देता है

मीडिया को व्यक्त की गई सीमित सीमा के अलावा किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। आशा और अपेक्षा है कि सार्थक बहस से सभी संभावित दृष्टिकोणों से इस मुद्दे की पूरी समझ बनेगी। [पैरा 34,35] [259-एच; 260-ए; 261-एफ-एच; 262-ए-सी] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[201
7] 9 एस सी आर।

प्रति चेलमेश्वर, जे। (अपने और गोगोई, जे. के लिए)

(पूरक)

1.1 एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप

अवमानकर्ता के लगातार संदिग्ध आचरण ने शायद भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस निष्कर्ष पर पहुँचाया कि उपरोक्त सभी प्रश्नों की न्यायिक पक्ष से इस न्यायालय द्वारा बेहतर जांच की जा सकती है। संदेह करने का कोई कारण नहीं है

अवमानना शुरू करने के लिए इस न्यायालय का प्राधिकरण/अधिकार क्षेत्र

कार्यवाही। काल्पनिक रूप से, यदि कोई यह आरोप लगाते हुए इस न्यायालय का रुख करता है कि न्यायमूर्ति के की गतिविधि इसके समान है न्यायालय की अवमानना और इसलिए उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, यह न्यायालय प्रश्नों की जांच करने के लिए बाध्य है। यह.

प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया हो सकता है। लेकिन इस अदालत का प्राधिकरण या अधिकार क्षेत्र ऐसी याचिका की जांच करने के लिए, यदि किया गया हो

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। इसलिए, यह तथ्य कि वर्तमान अवमानना कार्यवाही इस अदालत द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू की गई है

इसकी रखरखाव में कोई अंतर नहीं है। यदि केवल अवमानकर्ता ने कार्यवाही में उचित रूप से भाग लिया, तो उपरोक्त सभी उल्लिखित प्रश्नों और शायद उनके लिए कई और प्रासंगिक प्रश्नों की ठीक से जांच की जा सकती थी और आवश्यक भी।

निष्कर्षों को दर्ज किया जा सकता था। [पैरा 13] [265-एफ-जी]

1.2 दुर्भाग्य से, अवमानकर्ता ने कभी भी जांच की अनुमति नहीं दी

सही दिशा में। दूसरी ओर, उन्होंने अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाने का फैसला किया उनके खिलाफ इस आधार पर नहीं कि उनकी गतिविधि अवमानना नहीं है, बल्कि इस आधार पर कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ कोई अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। अवमानकर्ता के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ एकमात्र संभावित कानूनी कार्रवाई उन्हें पद से हटाने के लिए है।

संविधान के तहत निर्धारित महाभियोग की प्रक्रिया

उसका "आचरण" और "दुराचार" जो भी हो, एक ऐसा रुख जो स्पष्ट रूप से कानून में असमर्थनीय है। वह वहाँ नहीं रुका। उनका मानना था कि इस न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी

वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एक अपराध होगा।

अवमानक उन समुदायों में से एक से संबंधित है जो उस अधिनियम के सुरक्षात्मक छत्र के दायरे में आता है।

वह आरई में नहीं हैं, माननीय श्री जस्टिस सी. एस. कर्णन

केवल ऐसा माना जाता था, लेकिन कुछ आदेश पारित करने का भी इरादा था

जाहिरा तौर पर उस में निहित अधिकार के प्रयोग में जिसके आधार पर

विभिन्न कार्यों की शुरुआत करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति

उसके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण न्यायिक कार्रवाई के अलावा एक 1989 अधिनियम के तहत अपराध। [पैरा 14] [265-एच; 266-ए-डी]

1.3 अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने के अधिकार का प्रयोग न्यायपालिका द्वारा हमेशा से किया जाता रहा है। द.

उसके अस्तित्व का औचित्य यह नहीं है कि उसे संरक्षण दिया जाए

अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति से। उन्हें अधिक निश्चित नींव पर आराम करना चाहिए। नींव है- लोगों का विश्वास और विश्वास कि न्यायपालिका निडर और निष्पक्ष है। (पैरा 16] [266-एफ; 267-ए-बी] 1.4 अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति को हमेशा कुछ उच्च न्यायालयों में अंतर्निहित माना गया है और

अन्य इसे कानूनों द्वारा प्रदान किया गया था। ऐसी शक्ति का प्रयोग

न्यायपालिका के सदस्य हमेशा इस तथ्य के प्रति सचेत रहे हैं कि अवमानना की शक्ति का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए

देखभाल और सावधानी और केवल पूरी तरह से मजबूर करने वाली परिस्थितियों में इसके अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत अच्छा, न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, बल्कि अधिक विश्वास का भी जो इसके संपर्क में आने से उत्पन्न होता है भले ही मामूली रूप से अति-उत्साही हो, आलोचना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्याय कोई गुप्त गुण नहीं है। " [पारस 17,20] [267-बी; 269-सी]

1.5 भारत में न्यायालय को बदनाम करना अभी भी न्यायालय की अवमानना करने वाले कार्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि गतिविधि क्या है

जो न्यायालय के अपमान का गठन करता है, उसे उपर्युक्त मामलों में परिभाषित या बहुत सटीक रूप से समझाया नहीं गया है।

व्यक्तियों को इस आधार पर अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था कि उनके कार्यों ने अदालत को बदनाम किया था। [पैरा 24] [273-एफ]

1.6 किसी भी न्यायिक कार्यवाही के नियत समय के साथ हस्तक्षेप आपराधिक अवमानना का एक और पहलू है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट का संचालन

[201
7] 9 एस सी आर।

स्वतः संज्ञान अवमानना की शुरुआत के बाद अवमानकर्ता

विभिन्न आदेश पारित करने के उद्देश्य से 2017 की याचिका संख्या 1, जिनका विवरण निर्णय के पैराग्राफ में निहित है

भारत के मुख्य न्यायाधीश इस सवाल के बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं कि क्या इस तरह का आचरण देश के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के बराबर होगा। मुख्य बात

कार्यवाही अपराध का पता लगाने में समाप्त हो सकती है या नहीं भी हो सकती है

न्यायपालिका को बदनाम करने का अवमानक। अवमाननाकर्ता

न्यायालय के प्रारंभिक नोटिस द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अवमानना के आरोप को न्यायिक रूप से हल करने के सभी प्रयासों को निरस्त कर दिया गया। बल्कि, उन्होंने उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ अवमानना के आरोप की जांच करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए एक आलोचना में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने संबोधित किया था

पीठ के सदस्यों को कई लिखित संचार

मामले से निपटना और कई कथित मामले भी पारित किए थे

न्यायिक आदेश, जो, एक सरसरी नज़र में भी, प्रकृति और सामग्री में अवमाननापूर्ण हैं। "नोटिस के बाद" आचरण और अवमानकर्ता के कार्यों को अपेक्षा के न्यूनतम मानक द्वारा आंका जाना चाहिए, निश्चित रूप से, इस न्यायालय के समक्ष न्यायाधीश ने इसे पार कर लिया है।

अपेक्षित और अनुमेय अभिव्यक्ति के सबसे उदार मानक

सिस्टम। उन्होंने थोड़ा भी पछतावा नहीं दिखाया है जो हो सकता है एक शमन कारक बनें। यदि इस तरह के आचरण और कार्रवाई को बर्दाश्त किया जाता है, तो निश्चित रूप से प्रणाली में कमजोरी का एक तत्व दिखाई देगा; ऐसी किसी भी कमजोरी को प्रणाली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अवमानकर्ता का आचरण निश्चित रूप से न्यायालय को बदनाम करने के साथ-साथ इस न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के दोनों शीर्षों के तहत आने वाली आपराधिक अवमानना का गठन करता है। अतः अवमानकर्ता उत्तरदायी है।

इस न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित किया जाए। [पैरा 25] [274-ए जीजे

1.7 इस मामले का महत्व इससे भी आगे है

तत्काल समस्या। यह मामला दो बातों पर प्रकाश डालता है, (1) संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की आवश्यकता, उस मामले के लिए सभी स्तरों पर न्यायपालिका का कोई भी सदस्य; और (2) उपयुक्त कानून बनाने की आवश्यकता।

2 .

आरई में, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए शासन जहां एक संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण के लिए सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है

महाभियोग-लिया जाना है। [पैरा 26] [274-एच; 275-ए]

1.8 पीठ में उनकी पदोन्नति के बाद से अवमानक का आचरण विवादास्पद रहा है। जाहिर है, पदोन्नति के लिए अपने नाम की सिफारिश करते समय अवमानकर्ता के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में विफलता है। मकसद. उन व्यक्तियों की ओर उंगली उठाना नहीं है जो सिफारिश के लिए जिम्मेदार थे, बल्कि केवल इस तरह की सिफारिश करने के लिए एक उचित प्रक्रिया प्रदान नहीं करने की प्रणाली की विफलता को उजागर करना है।

मूल्यांकन। जिस उम्मीदवार पर विचार किया जा रहा है, उसके व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए कौन सा उपयुक्त तंत्र उपयुक्त होगा?

संवैधानिक न्यायालय के सदस्य के रूप में नियुक्ति एक ऐसा मामला है जिसकी पहचान सभी द्वारा उचित बहस के बाद की जानी चाहिए।

संबंधित-बार, बेंच, राज्य और सिविल सोसाइटी। लेकिन आवश्यकता निर्विवाद प्रतीत होती है। [पैरा 27] [275-बी-सी]

1.9 यह न्यायालय यह बताते हुए दुखी है कि इसके अलावा

इस पूरे प्रकरण ने भारतीय न्यायपालिका को शर्मिंदा किया है, इसके कुछ सदस्यों के आचरण के कई अन्य उदाहरण (दयालुता से जो जनता को कम ज्ञात हैं) हैं। न्यायपालिका जो निश्चित रूप से व्यवस्था के लिए कुछ शर्मिंदगी का कारण बनेगी। [पैरा 28] [275-डी]

1.10 संविधान के निर्माता देशभक्ति और परिपक्वता की महान भावना वाले लोग थे, पुरुष और महिलाएँ जिन्होंने इसे बनाए रखा। नागरिक नैतिकता के उच्च मानक। वे उन लोगों से उम्मीद करते थे जो

(दक्षता और अखंडता) उचित मानकों को नियोजित करके। द. संविधान निर्माता इस तथ्य से अवगत थे कि उच्च पदों पर आसीन होने के लिए हमेशा ईमानदारी और किसी भी संवैधानिक पद के पदधारी की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है

कार्यालय की प्रकृति और अपेक्षित आचरण के मानकों के साथ असंगत व्यवहार का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद, भारत के राष्ट्रपति से शुरू होकर विभिन्न संवैधानिक पदों के धारकों के खिलाफ महाभियोग के लिए संविधान में प्रावधान किए गए। [पैरा

29] [275 - ई-जी] सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[201
7] 9 एस सी आर।

1.11 जब संविधान के सदस्यों की बात आई

अदालतों में समान रूप से, यह कल्पना की गई थी कि ऐसे अवसर हो सकते हैं। लेकिन न्यायाधीशों के महाभियोग के लिए मानक और प्रक्रियाएँ हैं -

स्पष्ट कारणों के लिए बहुत अधिक कठोर। संवैधानिक न्यायालयों के पदों के धारकों के आचरण में विचलन हो सकते हैं जो व्यक्ति के महाभियोग की सख्ती से मांग नहीं करते हैं या ऐसा महाभियोग संभव नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे मामलों से निपटने के अन्य तरीके भी होने चाहिए। संविधान का मूल पाठ है -

इस बारे में चुप रहें। [पैरा 30] [275-एच; 276-ए]

उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम

भारत संघ (1993) 4 एससीसी 441: [1993] 2 पूरक।

एस. सी. आर. 659; 1998 का विशेष संदर्भ संख्या 1 (1998) 7

एससीसी 739: [1998] 2 पूरक। एस. सी. आर. 400 (ई. एम. शंकरन)

नम्बूदरीपद बनाम। टी. नारायणन नांबियार (1970) 2 एससीसी

325 : [1971] 1 एससीआर 697; आर. एल. कपूर बनाम मद्रास राज्य

(1972) 1 एससीसी 651: [1972] 3 एससीआर 417; प्रीतम पाल बनाम।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर 1993 सप्लीमेंट।

(1) एससीसी 529: [1992] 1 एस. सी. आर. 864; श्री बरदकांत

मिश्रा बनाम। उड़ीसा उच्च न्यायालय के पंजीयक और अन्य

(1974) 1 एससीसी 374: [1974] 2 एस. सी. आर. 282-संदर्भित।

रेक्स वी. एल्मन (1765) विल्मोट्स नोट्स, 243; क्रेग बनाम। हार्नी, 331 यू $367,376 (1947); हेल्मोर बनाम। स्मिथ,

(1887) 35 Ch D 449,455; विधि आयोग की रिपोर्ट

अदालत की अवमानना पर यूनाइटेड किंगडमः घोटालेबाजी करना

न्यायालय (न्यायालय की अवमाननाः अदालत को बदनाम करना ", (2012) द लॉ कॉम No.335 [लंदन "

स्टेशनरी कार्यालय)]-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1993] 2 पूरक। एससीआर 659

पै
रा 2

संदर्भित किया गया है
संदर्भित किया गया है

[1998] 2 पूरक। एससीआर 400

पै
रा 2

[1971] 1 एससीआर 697

संदर्भित किया गया है

पै
रा 18

[1972] 3 एससीआर 417

संदर्भित किया गया है

पै
रा 19

[1992] 1 एससीआर 864

संदर्भित किया गया है

पै
रा 19

[1974] 2 एससीआर 282

संदर्भित किया गया है

पैरा 20 इन आरई, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः सुओ मोटू अवमानना

2017 की याचिका (सिविल) संख्या 1।

मनिंदर सिंह, एएसजी, राकेश द्विवेदी, के. के. वेणुगोपाल,

रूपिंदर सिंह सूरी, अजीत के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , चंचल के. आर. गंगुली, सुश्री नर्मदा, सुश्री माधवी दीवान, नलिन कोहली, सुश्री रंजीता रोहतगी, प्रभाष बजाज, निखिल नय्यर, एन. साई विनोद, सुश्री स्मृति शाह, दिव्यांशु राय, गौरव भाटिया, एम. योगेश कन्ना, सुश्री निथ्या, श्रीमती महा लक्ष्मी, पार्थ सारथी, सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री आकांक्षा चौधरी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई

1. हमारे हाथों में काम अप्रिय है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यों से संबंधित हैः तत्काल कार्यवाही श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन द्वारा की गई आपराधिक अवमानना की कथित कार्रवाइयों से संबंधित है। द.

वर्तमान कार्यवाही का स्वतः संज्ञान लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में

इस अदालत को अगला कदम उठाना है, जिससे उसे दोषी ठहराया जा सके और सजा सुनाई जा सके, अदालत निस्संदेह कुंवारी हो गई होगी

क्षेत्र। ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन तब, न्याय के प्रशासन की प्रक्रिया में, व्यक्ति की पहचान, स्पष्ट रूप से अप्रासंगिक है। इस न्यायालय को गुण-दोषों का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है

मामले के तथ्यों के आधार पर उसके सामने रखे गए विवाद। इससे उम्मीद की जाती है कि वह बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या पक्षपात के अपने निष्कर्षों को दर्ज करेगा।

बीमार-इच्छा।

2. सुनवाई के दौरान इस मामले में जो तथ्यात्मक स्थिति सामने आई, वह लगभग पूरी तरह से विषय-वस्तु पर आधारित थी।

न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा संबोधित पत्राचार। अंततः उनका मद्रास उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो गया। उनके स्थानांतरण की घटना से पहले मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की एक श्रृंखला ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशों को उनके स्थानांतरण की मांग करते हुए पत्र लिखे थे। श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन के स्थानांतरण की भी मांग एक संयुक्त ज्ञापन के माध्यम से की गई थी।

मद्रास उच्च न्यायालय के 20 वर्तमान न्यायाधीशों द्वारा संबोधित प्रतिनिधित्व।

3. इस अवधि के दौरान, और उनके स्थानांतरण की मांग के कारणों से असंबद्ध, मद्रास उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने संपर्क किया

इस न्यायालय ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन ने पहल की थी

स्वतः संज्ञान की कार्यवाही, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय की रिपोर्ट के प्रशासनिक आदेशों पर रोक लगा दी थी

[201
7] 9 एस सी आर।

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित। सुना है।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस न्यायालय की एक पीठ ने निम्नलिखित निर्देश पारित किएः -

" विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है।

नोटिस जारी करें।

इस बीच, दिनांकित अंतरिम आदेश पर रोक होगी।

30.4.2015 एम. पी. नं. में पारित। 1 2015 में सुओ-मोटो रिट याचिका सं। (2015 का), अगले आदेश तक।

हम रोकते हैं-विद्वान न्यायाधीश, जिन्होंने कार्यवाही शुरू की है

स्वतः संज्ञान रिट याचिका सं। (मद्रास में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 2015 का) दोनों में से

उक्त याचिका और अन्य मामलों में सुनवाई या कोई निर्देश जारी करना इसके साथ जुड़ा हुआ है।

किसी भी व्यक्ति/प्राधिकारी द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा या

कनिष्ठ प्रभागीय न्यायिक के चयन और नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया को पूरा करने में विद्वान न्यायाधीश

विशेष अनुमति याचिका के निपटारे तक अधिकारी।

गर्मी की छुट्टियों के बाद सूची बनाएँ। "

4. इस न्यायालय के हस्तक्षेप से विचलित हुए बिना, न्यायमूर्ति श्री सी. एस. कर्णन ने उच्च न्यायालय में अपने सहयोगियों को गाली देना जारी रखा। मद्रास, उच्चतम कार्यपालक को संचार को संबोधित करके और

न्यायिक अधिकारी। हम केवल उन लोगों का उल्लेख करेंगे जो मामले के रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं। हम संक्षिप्तता के कारण अतीत को छोड़ सकते हैं, और

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित उनके दिनांकित 21.8.2015 पत्र से शुरू करें। उपरोक्त संचार का अवलोकन,

उचित कार्य न सौंपे जाने पर अपने असंतोष को प्रकट करता है

रोस्टर, जब उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में प्रतिनियुक्त किया गया था। यहां तक कि जब वे तीन महीने की अवधि के बाद प्रधान पीठ में लौटे, तब भी वे उन्हें सौंपे गए रोस्टर से नाखुश थे। तत्काल पत्र में, उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की, जब मूल रूप से उन्हें सौंपे गए मामलों को मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनके बोर्ड से छीन लिया गया था

मद्रास उच्च न्यायालय से, और अन्य पीठों को सौंपा गया। उपरोक्त व्यक्तिगत शिकायतों के अलावा, उन्होंने सीधे और स्पष्ट आरोप लगाए (में श्री जस्टिस के खिलाफ उनका उपरोक्त पत्र दिनांक 21.8.2015)। वी. डी. "., इन आर. ई. के लिए, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

थ.

(जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के बावजूद (न्यायमूर्ति कर्णन के अनुसार) उनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं थी पद के लिए योग्यता। वास्तव में, यह आरोप लगाया गया था कि उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी थे। यह भी आरोप लगाया गया था (उपरोक्त दिनांकित पत्र में)

21.8.2015) कि डिवीजन बेंच के न्यायाधीश-डॉ. जस्टिस "... टी. वी". और श्री न्याय "। सी. टी. एस. ने अपनी न्यायिक प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया था।

स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के कहने पर आदेश पारित कर रहा था। उन्होंने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर अपने द्वारा पारित स्वतः संज्ञान आदेशों के खिलाफ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का भी आरोप लगाया। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के हाथों की पहल (सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने के लिए)

उन्हें उच्च न्यायालय की प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए गठित किसी भी समिति में शामिल किया गया था। इस वजह से उन्होंने मुख्य न्यायाधीश पर एक कम विशेषाधिकार प्राप्त जाति से संबंधित होने के कारण उन्हें अलग करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने एक

राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को इस संबंध में शिकायत

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। न्यायमूर्ति कर्णन ने मद्रास उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (उपरोक्त संचार में) पर उच्च न्यायालय में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने का भी आरोप लगाया।

इस ओर से उनका तर्क था कि उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करते हुए उन्नत समुदायों का पक्ष लिया और साथ ही साथ वंचित जातियों और जनजातियों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों की भी अनदेखी की। दिनांक 1 के पत्र का समापन करते हुए, न्यायमूर्ति श्री सी. एस. कर्णन ने व्यक्त किया कि मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत अपराध किए थे।

जिन्होंने कुछ न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, विशेष रूप से श्री जस्टिस के खिलाफ। ...... V.R.S.M... "। संवाद दिलचस्प है, क्योंकि गृह सचिव को उनके पत्र को "स्वतः संज्ञान न्यायिक आदेश" के रूप में मानने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त पत्र में न्यायमूर्ति कर्णन ने मद्रास उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था

[201
7] 9 एस सी आर।

याचिका (-5.2.2016 दिनांकित पत्र), एक संख्या। दिनांकित 5.2.2016 पत्र में निहित निर्देश में गृह सचिव से पूर्व-उल्लिखित अधिवक्ता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता थी।

6. श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को एक और पत्र लिखा।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 10.2.2016 पर। पल भर में उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य न्यायिक के क्षेत्रीय केंद्रों के उद्घाटन के लिए एक समारोह की व्यवस्था की थी

कोयंबटूर और मदुरै में अकादमी (-21.2.2016 पर)। उन्होंने आरोप लगाया।

मुख्य न्यायाधीश, केवल उच्च जाति के न्यायाधीशों को भाग लेने की अनुमति देने के लिए

कार्य को। यह बताया गया कि उत्सव में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई प्रतिनिधित्व शामिल नहीं था। आरोप लगाया गया था,

कि भले ही उनका नाम शुरू में शामिल किया गया था, लेकिन उनकी जगह एक कनिष्ठ उच्च जाति के न्यायाधीश ने ले ली। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि उन्होंने

इस मुद्दे पर बार-बार आंदोलन करना, पहले के अवसरों पर भी। पल भर में

दिनांक 10.2.2016 का संचार, न्यायमूर्ति कर्णन ने फिर से प्रमुख घोषित किया

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एक अपराधी।

7. उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं। 14842 2015 का

मद्रास उच्च न्यायालय के महापंजीयक द्वारा दायर (ऊपर पैराग्राफ 3 देखें)। आई. ए. नहीं। 6 वर्ष 2016 को पंजीयक द्वारा 12.2.2016 पर दाखिल किया गया था।

मद्रास उच्च न्यायालय के जनरल, तत्काल निर्देशों के लिए। उक्त में आवेदन, संदर्भ पहले दिनांकित 30.4.2015 पारित आदेश के लिए किया गया था

न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा, जिस पर इस न्यायालय द्वारा 11.5.2015 (उपरोक्त पैराग्राफ 3 में निकाला गया आदेश) पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद न्यायमूर्ति कर्णन ने संबोधित किया

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 21.8.2015 दिनांकित एक पत्र (ऊपर वर्णित विवरण)। श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन ने फिर से कथित रूप से स्वतः संज्ञान न्यायिक शक्ति (ऊपर व्यक्त विवरण) का प्रयोग करते हुए दिनांकित एक पत्र को संबोधित किया। इसे भी उजागर करने की मांग की गई थी

आई. ए. नहीं। 6 2016 में न्यायमूर्ति कर्णन ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित एक समारोह के संबंध में आपत्ति जताई थी। तमिलनाडु राज्य न्यायिक अकादमी के साथ कोयंबटूर और मदुरै में क्षेत्रीय केंद्रों का उद्घाटन करने के लिए, जो 21.2.2016 के लिए निर्धारित है। न्यायमूर्ति कर्णन ने इसमें आरोप लगाया था कि उन्हें न्यायिक अकादमी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य के रूप में हटा दिया गया था। होना चाहा गया था

समझाया (आई. ए. में नहीं। 6 2016), कि श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन द्वारा लगाए गए आरोप गलत थे, क्योंकि उन्हें कभी भी गलत नहीं माना गया था। 2001 में अपनी स्थापना के बाद से न्यायिक अकादमी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य के रूप में नामित। आई. ए. नं. की सामग्री।

6 इन आरई, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

2016 , श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन द्वारा पारित एक अन्य कथित स्वतः संज्ञान न्यायिक आदेश का भी संदर्भ दें, जिसमें तमिलनाडु राज्य के गृह सचिव को एक व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। श्री पीटर रमेश कुमार ने मद्रास उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों से इस आधार पर कहा कि उन्हें अपनी जान से मारने की धमकी मिल रही है।

स्पष्ट रूप से श्री जस्टिस "नाम दिया गया। वी. आर. "(ऊपर वर्णित विवरण)। उपरोक्त आदेश पारित करने की पृष्ठभूमि को समझाने की मांग की गई थी

आई. ए. सं. के पैरा 10 में। 6 2016 का, निम्नानुसारः

" उपरोक्त आदेश निम्नलिखित पृष्ठभूमि में पारित किया गया है,

नीचे सूचीबद्ध किया गया हैः

(a) 16.9.2015 पर। डब्ल्यू. पीटर रमेश कुमार के साथ कुछ अधिवक्ता कोर्ट हॉल नं. 2 मदुरै पीठ की, और इच्छुक अधिवक्ताओं को माननीय को संबोधित करने से रोक दिया

बहिष्कार के आह्वान को लागू करने के लिए बेंच। इसके अलावा, संबंधित अधिवक्ता ने माननीय पीठ को कोई भी कार्रवाई करने की धमकी दी उसके खिलाफ। नतीजतन, डिवीजन बेंच को मजबूर होना पड़ा

उसके कुकर्मों के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करें।

(ख) उपरोक्त नामित अधिवक्ता को पहले भी कई मौकों पर अवमानना के लिए घसीटा गया था। तीन साल पहले उच्च न्यायालय ने राज्य बार काउंसिल को अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था

दुराचार के लिए कार्यवाही। इससे पहले, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने उन्हें अवमानना का दोषी पाया था और उन्हें परिवीक्षा पर रखा था

एक वर्ष की अवधि के लिए। फिर भी, संबंधित अधिवक्ता ने इस दौरान भी विघटनकारी प्रथाओं में लिप्त रहना जारी रखा

परिवीक्षा और मामला विचाराधीन है पूर्ण बेंच।

(ग) 30.11.2015 पर, सुओ-मोटो कॉन्ट। याचिका (एम. डी.) सं. 1449 2015 का, दिनांक 16.9.2015 के आदेश के अनुसार पंजीकृत

मदुरै पीठ द्वारा पारित, श्री न्यायमूर्ति के समक्ष पहली बार सुनवाई के लिए आया। आर. एस. "और माननीय मिस्टर जस्टिस". एम. वी. वी. "। उपरोक्त नामित अधिवक्ता ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। हालांकि,

कथित समकालीन ने डिवीजन बेंच के पीठासीन न्यायाधीश के खिलाफ आपत्तिजनक और जातिवादी आरोप लगाए

उनके जवाबी हलफनामे में कार्यवाही। आरोप है कि

समकालीन ने विद्वान न्यायाधीश के संबंध में कुछ महिला वकीलों के खिलाफ झूठे और निंदनीय आरोप भी लगाए।

उन्होंने आगे हलफनामे की सामग्री को प्रसारित किया जिसमें शामिल हैं -

सुओ-मोटो कॉन्ट को स्थानांतरित किया गया। याचिका (एम. डी.) सं. 1449 की प्रधान पीठ पर एक विशेष रूप से गठित पीठ के समक्ष 2015 का उच्च न्यायालय। इस बीच, कथित समकालीन ने भद्दे और आपत्तिजनक संदेशों को प्रसारित करना जारी रखा

उपरोक्त अवमानना की सुनवाई करने वाले माननीय न्यायाधीशों के विरुद्ध

याचिका, सोशल मीडिया के माध्यम से।

(ई) 4.2.2016 पर, डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ आरोप तय किए।

उसे आपराधिक अवमानना कार्यवाही में और प्रतियां प्रदान की गईं उस पर लगे आरोप। आरोपों की प्रति प्राप्त होने पर, उन्होंने एक प्रतिबंधित नेता के दिवंगत नेता की प्रशंसा करते हुए नारे लगाए।

संगठन किया और न्यायाधीशों के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी भी की। हालाँकि, पीठ ने मामले को 15.2.2016 के लिए पोस्ट किया

आरोपों पर अवमानकर्ता का जवाब। (च) 5.2.2016 पर, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने पारित किया

संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ आपत्तिजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने और प्रसारित करने से रोकने का आदेश छह संबंधित महिला वकीलों के एक समूह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर बार की महिला सदस्य

ये आरोप। इसके अलावा, वकीलों के सभी चार संघ

मदुरै में अभद्रता की निंदा करने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए

कथित समकालीन द्वारा संचालित अभियान और आग्रह किया उच्च न्यायालय और राज्य बार काउंसिल उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।

अंत में यह बताया गया कि मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी रोस्टर के संदर्भ में, 1.2.2016 से प्रभावी, न्यायमूर्ति कर्णन को आपराधिक पुनरीक्षण-प्रवेश और अंतिम सुनवाई, और विशेष रूप से आदेशित मामलों की सुनवाई करने का काम सौंपा गया था। यह बताया गया कि न्यायमूर्ति कर्णन रोस्टर की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए आदेश पारित कर रहे थे

उसे सौंप दिया। यह भी कहा गया कि न्यायमूर्ति कर्णन बार-बार हस्तक्षेप कर रहे थे या मुद्दों को फिर से खोल रहे थे, यहां तक कि उच्च न्यायालय की अन्य पीठों के समक्ष वर्तमान में लंबित मामलों में भी। इस पर प्रकाश डाला गया,

कि उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित न्यायिक कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी

अदालत। आई. ए. में नहीं। 6 2016 में, मद्रास उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के माध्यम से उचित निर्देश मांगेः

आरई में, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

" प्रार्थना करें

परिसर में, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय

न्यायालय इस बात से प्रसन्न हो सकता हैः

(क) स्वतः संज्ञान न्यायिक आदेशों के संचालन पर रोक लगाएँ

5 / 8.2.2016 (अनुलग्नक ए-6) और 10.2.2016 (अनुलग्नक ए-4) पारित हो गए।

मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. एस. कर्णन द्वारा; (ख) माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. एस. कर्णन को किसी भी प्रकार का प्रयोग न करने का निर्देश दें।

उच्च न्यायालय की स्वतः संज्ञान शक्तियाँ या मद्रास उच्च न्यायालय के पंजीयक को ऐसे स्वतः संज्ञान आदेशों को दर्ज करने का निर्देश देना जो स्वतः संज्ञान के अनुसार हों।

मोटु रिट याचिकाएँ;

(ग) माननीय न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन को सुनवाई या निर्देश जारी करने या किसी भी तरह से संबंधित या संबंधित होने से रोकें।

स्वतः संज्ञान न्यायिक आदेश दिनांक 5/8.2.2016 से संबंधित कार्यवाही और

10.2.2016 मद्रास में न्यायपालिका का उच्च न्यायालय;

(घ) ऐसे अन्य और आगे के आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

उपरोक्त आई. ए. में सुनवाई के दौरान नहीं। 6 2016 का

(जिसमें हममें से एक-जगदीश सिंह खेहर और श्रीमती आर. भानुमति, जे. जे.। , पीठ के सदस्य थे), न्यायालय को सूचित किया गया कि श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन को मद्रास उच्च न्यायालय से उनके स्थानांतरण का प्रस्ताव पहले ही प्राप्त हो चुका है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित पारित कियाः

15.2.2016 पर आदेश देंः

" श्री के. के. वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रवेश किया

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थिति ने हलफनामा दायर किया है

श्रीमान "। बी. एच. ", पंजीयक-सह-निजी सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय, दिनांक 14.02.2016। उसी के अवलोकन से पता चलता है कि माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. एस. कर्णन को उच्च न्यायालय से उनके स्थानांतरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

उचित है कि माननीय न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन को सुनना चाहिए और केवल ऐसे मामलों का निपटारा करें जो मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें विशेष रूप से सौंपे गए हैं। यह उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के लिए खुला रहेगा, न कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट सौंपने के लिए।

[201
7] 9 एस सी आर।

उसके लिए कोई और प्रशासनिक/न्यायिक कार्य। इसका मतलब होगा।

कि कोई अन्य आदेश माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. एस. कर्णन द्वारा, स्वतः या अन्यथा, किसी ऐसे मामले में पारित नहीं किया जाएगा जो विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं है। उसे।

पारित सभी या किसी भी प्रशासनिक/न्यायिक आदेश (आदेशों) का संचालन

माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. एस. कर्णन द्वारा जारी किए जाने के बाद

मद्रास उच्च न्यायालय से उनके स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांकित

12.02.2016 . (जब तक कि उसे विशेष रूप से नहीं सौंपा गया हो। माननीय प्रमुख द्वारा

न्याय), अगले आदेश तक रोक रहेगा।

तत्काल आदेश की एक प्रति माननीय श्री को सौंपी जाएगी।

उच्च न्यायालय के महापंजीयक द्वारा न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन। यह माननीय न्यायाधीश के लिए पहले उपस्थित होने के लिए खुला होगा

इस न्यायालय को, यदि उसे इस प्रकार की सलाह दी जाती है (तत्काल/के संबंध में)

लंबित मामला) "।

8. अगला प्रासंगिक पत्र न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा जारी किया गया था।

26.10.2016 . यह शहर के पुलिस आयुक्त को संबोधित किया गया था, जिसके लिए आवश्यक था आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए। तत्काल पत्र में न्यायमूर्ति कर्णन ने दावा किया कि

सामाजिक और जातिगत भेदभाव का शिकार होना। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि

रैगिंग और अपमानजनक कार्यों के कारण पीड़ा का सामना करना पड़ा था, श्री न्यायमूर्ति "F.M.I.K"... के नेतृत्व में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। रैगिंग के इन आरोपों को उन्होंने चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया था, जो इस प्रकार हैंः

" रैगिंग न्यायाधीशों द्वारा सामाजिक बहिष्कार को इन रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है

निम्नलिखित चार श्रेणियाँः

1. नीचे उल्लिखित न्यायाधीशों ने सीधे मेरा अपमान किया

सार्वजनिक परिसरों में, अर्थात् श्री न्यायमूर्ति "। आई. के. ", मिस्टर जस्टिस"... एन. एन. ", मिस्टर जस्टिस"। आर. एस. ", जिसे अब तैनात किया गया है

जम्मू और कश्मीर, मिस्टर जस्टिस "। के. एन. बी. ", मिस्टर जस्टिस"।

आर. एस. एम. ". अब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तैनात कोर्ट, मिस्टर जस्टिस ". ए. ए".., मिसेज जस्टिस "... ए. जे.। .. ", मिस्टर जस्टिस". एन. के. "., मिस्टर जस्टिस". एस. एम. के. ". और मिस्टर जस्टिस". एम. एस. . "नीचे तीन न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया है". एम. वाई. ई.

...... " , अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति "। आर. के. ए. ", अब सुप्रीम कोर्ट के सेवारत न्यायाधीश और मिस्टर जस्टिस"। एस. के. के. ", जिन्होंने अपना सहयोग भी बढ़ाया। मद्रास उच्च न्यायालय के रैगिंग न्यायाधीशों के साथ आरई में काम करते हुए, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

प्रशासनिक शक्ति और सार्वजनिक संस्थान में मेरा अपमान किया /

न्यायपालिका, उस प्रभाव के लिए मैंने उनके खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत शिकायतें दर्ज की हैं जो संबंधित उच्च गणमान्य कार्यालयों में जांच लंबित है। अब आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त सभी तीन न्यायाधीशों को न्यायाधीशों की पहली श्रेणी के साथ शामिल करें और एक एफ. आई. आर. पंजीकृत करें।

तदनुसार और सटीक रूप से। मेरे खिलाफ आरोप साबित करने के लिए न्यायाधीशों ने कहा, फाइल पर भौतिक साक्ष्य उपलब्ध हैं

मद्रास उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री।

2. दूसरी श्रेणी के न्यायाधीश अप्रत्यक्ष रूप से अपना कार्यकाल बढ़ाते हैं।

सामाजिक बहिष्कार और शारीरिक रूप से रैगिंग के लिए सहयोग स्थानों पर उपस्थिति।

3. तीसरी श्रेणी हँसी और शारीरिक रूप से आनंद ले रही थी।

हाव-भाव, और

4. न्यायाधीशों की चौथी श्रेणी ने अपनी खामोशी बनाए रखी और

उनके खिलाफ उनके कार्यों के बारे में उनकी घबराहट दिखाई दी मुझे "।

उपरोक्त आक्षेपों के आधार पर, न्यायमूर्ति कर्णन ने

चेन्नई शहर के पुलिस आयुक्त से अनुरोधः

" अब मैं आपसे सामाजिक बहिष्कार सहित रैगिंग अधिनियम के तहत रैगिंग न्यायाधीशों की पहली श्रेणी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का अनुरोध करता हूं। गलती करने वाले अन्य न्यायाधीशों को बाद में शामिल किया जाएगा।

जांच पड़ताल की। अभियुक्त व्यक्तियों/न्यायाधीशों के खिलाफ अभियोजन मामला स्थापित करने के बारे में मेरा विचार जिसके लिए मैं तत्काल मामले में एक प्रमुख भूमिका निभाता हूं। एक सक्षम अधिकारी के रूप में संबंधित आपराधिक न्यायालय के समक्ष इस तरह के बड़े अपराधों को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए आपकी भूमिका केवल मामूली है। अपनी शिकायत के अनुसार, मैं एक याचिका दायर करूंगी।

अपराध वास्तव में एक दलित न्यायाधीश के खिलाफ एक सार्वजनिक अपराध है और यह मामला गलती करने वालों के खिलाफ संसद के समक्ष भी रखा जाएगा। न्यायाधीश आवश्यक औपचारिकताओं को देखने के बाद। ”

9. न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा राज्य लोक अभियोजक, आर. ए. एस. उच्च न्यायालय, चेन्नई को संबोधित एक पत्र का भी संदर्भ दिया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि उन्होंने श्री न्यायमूर्ति के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायिक आदेश पारित किया था।

[201
7] 9 एस सी आर।

उनकी नियुक्ति के लिए फर्जी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। उपरोक्त पत्र में यह भी बताया गया था कि मामले की जांच लंबित है।

मद्रास उच्च न्यायालय, उक्त श्री न्यायमूर्ति ". एन. डी"... को बचा रहा था। इस पर भी प्रकाश डाला गया। वह श्री न्याय "। एस. के. के.-मद्रास उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे थे। और अनुसूचित जातियों के तहत अपराध करने के लिए भी

और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989। उन्होंने यह भी बताया कि मद्रास उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने

श्री हाथी राजेंद्रन को उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए नियुक्त किया गया, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त अधिवक्ता एक हत्या में शामिल था

मामला। यह भी आरोप लगाया गया था कि एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था कथित अधिवक्ता के खिलाफ, जालसाजी करने के लिए। अपने पत्र में उन्होंने कहा,

न्यायमूर्ति कर्णन ने लोक अभियोजक से उपरोक्त मामलों का विवरण एकत्र करने और उनकी सहायता से जांच करने का अनुरोध किया था

राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी। उन्होंने राज्य लोक अभियोजक से जांच के परिणाम उन्हें भेजने का भी अनुरोध किया था, इसलिए कि वह इसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

10. जस्टिस कर्णन ने 23.1.2017 दिनांकित एक अन्य पत्र के माध्यम से इस पर प्रकाश डाला

उच्च न्यायालय में भ्रष्टाचार, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित न्यायाधीशों के हाथोंः

" 1. मिस्टर जस्टिस "। एस. के. के. ";

2. मिस्टर जस्टिस ". एस. एम. के.

3. मिस्टर जस्टिस "। V.R.S.M..

4. श्रीमती जस्टिस ". सी. वी"..;

5. मिस्टर जस्टिस "। आर. एस. आर. "
6. मिस्टर जस्टिस "। आर. के. ए. ";

7. मिस्टर जस्टिस "। टी. एस. टी. टी. एस. टी. ";

8. मिस्टर जस्टिस "... एम. वाई. आई".;
9. मिस्टर जस्टिस "। आई. के. ";

10. मिस्टर जस्टिस ". ए. के.

ई. डी. आर ई. डी. आर 99 "।

11. मिस्टर जस्टिस "।

12. मिस्टर जस्टिस "।

के. एन. बी. ";

13. मिस्टर जस्टिस "... ए. ए".।

14. श्रीमती न्याय "। ए. जे. ";

15. मिस्टर जस्टिस "। वी. डी. "; आरई में, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन [जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

17. मिस्टर जस्टिस "। एन. के. ";
18. मिस्टर जस्टिस "... एन. एन..... 92.

19. मिस्टर जस्टिस "। टी. आर. ";

20. मिस्टर जस्टिस "... एस"..।

तत्काल दिनांकित 23.1.2017 पत्र का न्यायमूर्ति कर्णन ने समर्थन किया था।

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबद्ध निजी सचिव-सह-पंजीयक श्री एच. "., पंजीयक

मद्रास उच्च न्यायालय के, और श्री को भी। एस. पी. एस. पी. ", अधिवक्ता-अध्यक्ष, तमिलनाडु अधिवक्ता संघ।

11. श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन की मानसिकता एक से उभरती है

उनके द्वारा भारत के प्रधान मंत्री को संबोधित दिनांक 3.1.2017 का संचार। इसकी सामग्री का सारांश दर्ज करने के बजाय इसे नीचे निकालना उचित होगा, जैसा कि अब तक किया गया है।

इससे पहले। 3.1.2017 दिनांकित उपरोक्त संचार का पाठ तदनुसार नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया निम्नलिखित पर ध्यान देंः

1. मिस्टर जस्टिस "। टी. एस. टी. ", भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश

3.1.2017 पर सेवानिवृत्ति के लिए आता है। विद्वान न्यायाधीश ने उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के प्रस्ताव के रूप में न्यायाधीशों की विभिन्न सूचियाँ भेजी थीं। इस सूची में पर्याप्त डी. ए. एल. आई. टी. प्रतिनिधित्व शामिल नहीं है, न ही मुस्लिम और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदायों से। प्रस्तावित सूची वित्तीय रूप से मजबूत उम्मीदवारों से बनी है।

विशेष रूप से उच्च जाति और कुलीन वंशानुगत उम्मीदवारों से। इस तरह का चयनात्मक विकल्प उपयुक्त नहीं है।

लोकतांत्रिक देश और न्यायपालिका का अनुपयुक्त होना क्योंकि यह स्पष्ट रूप से भेदभाव की ओर इशारा करता है।

2. मिस्टर जस्टिस "। टी. एस. टी. ", सीजेआई, एक महत्वपूर्ण बैठक में जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्री और

विभिन्न उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीशों ने मुलाकात की। इसके बाद इस सीजेआई के रोते हुए नाटक को देखते हुए, 125 करोड़ की भारतीय आबादी सीजेआई के रवैये को निर्धारित करने में असमर्थ है क्योंकि वह कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कानून और न्याय बनाए रखने के लिए पूरी न्यायपालिका के शीर्ष अधिकारी हैं।

3. उपर्युक्त माननीय न्यायाधीश रोते हुए पाए गए, फिर भी एक और क्षण में संघ के खिलाफ गुस्से का प्रकोप दिखा रहा है :

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 9 एस सी आर।

गुजरात में एक अन्य स्थान पर न्यायाधीशों की सूची को मंजूरी देने के लिए सरकार ने केंद्र सरकार की सराहना की। इस तरह का असंतुलित दुष्चक्र गिरगिट छिपकली के समान है। जो विभिन्न रंगों के माध्यम से यादृच्छिक रूप से अपना रंग बदलता है। एक शीर्ष गणमान्य व्यक्ति का यह अनियमित व्यवहार हमारी करोड़ों की भारतीय आबादी के विशाल वर्ग के दिमाग को चौंका रहा है।

4. श्री न्यायमूर्ति 56 "... टी. एस. टी".., सी. जे. आई. और न्यायमूर्ति "... एसकेके।

32

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मिलीभगत ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया

में कानूनी सहायता केंद्र के उद्घाटन में भाग लेना कोयंबटूर। इस तरह उन्होंने मुझे एक में शामिल होने से भेदभाव किया

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के बावजूद सार्वजनिक कार्य। दोनों समारोह की अध्यक्षता करने वाले मुख्य अतिथि थे। इसलिए, मैंने उनके खिलाफ प्रारंभिक कानूनी कार्रवाई शुरू की

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम। यह वास्तविक आरोप दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित होगा।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अलावा मद्रास उच्च न्यायालय रजिस्ट्री की फाइल पर पहले से ही उपलब्ध है। 5. मिस्टर जस्टिस "। टी. एस. टी. ", जिन्होंने मौखिक रूप से श्री जस्टिस को मेरे घोषित निर्णयों को रखने का आदेश दिया।" एस. के. के. "। मुखिया।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बिना किसी वैध नियुक्ति के

पूछताछ या किसी भी कानूनी अनंतिम आवश्यकता जैसे नियम। के रूप में

इन दोनों ने एक सार्वजनिक संस्थान में मेरा अपमान करके संयुक्त रूप से सांठगांठ का सहारा लिया है। इस प्रकार, पंजीयक (न्यायिक) सहित दोनों, मद्रास उच्च न्यायालय एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराधी हैं। श्री.

न्याय "। टी. एस. टी. ने मनगढ़ंत शिकायतों पर मेरे खिलाफ जांच का आदेश दिया जिसका मैं अब सामना कर रहा हूं। उस जाँच में दोनों ने कहा

न्यायाधीशों को सह-उत्तरदाताओं के रूप में शामिल किया गया है जिनमें शामिल हैं - पंजीयक (न्यायिक)। जाँच रिपोर्ट के बाद आगे की चर्चा के लिए संसद को भेजा जा रहा है ताकि वास्तविक स्थिति का निर्धारण किया जा सके।

महाभियोग के लिए व्यक्ति। इन परिस्थितियों में। मैं भारत के माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवलोकन को रद्द कर दें और

वर्तमान सी. जे. आई. द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद उपयुक्त पद के लिए किसी भी अस्थायी योजना पर विचार करना। इस तरह मामला रखा जा सकता है

मुझे। 6. इसी तरह श्री न्यायमूर्ति "। एस. के. के. ", मुख्य न्यायाधीश

मद्रास उच्च न्यायालय के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जा सकता है जैसा कि आई. एन. आर. ई., माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन में उल्लिखित है।

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

(5) सी. जे. आई. के साथ सांठगांठ करने के लिए और उसे किसी भी अस्थायी पदोन्नति की प्रतीक्षा करने के लिए भी जब तक कि भ्रष्टाचार के आरोपों सहित मेरे आरोप साफ नहीं हो जाते। 7. मेरी महत्वपूर्ण स्थिति मुझे रोकती है और मैं न्यायपालिका के तथ्यों और परिस्थितियों को पूरी तरह से पूरे देश के सामने प्रकट करने में असमर्थ हूं क्योंकि मैं न्यायपालिका की बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं।

न्यायाधीश और यह मेरा परम कर्तव्य है कि हम हर समय अपने न्यायालयों की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखें। हालांकि, कई न्यायाधीशों द्वारा लगातार की जा रही अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, जिससे न्यायपालिका को लाइलाज नुकसान हो रहा है। में नहीं कह सकता।

मद्रास उच्च न्यायालय में क्या चल रहा है, यह सार्वजनिक करें। अवमूल्यन का सबसे निचला स्तर और दुख की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समर्थन का लाभ दिया गया।

8. भारतीय संवैधानिक कानून के अनुसार न्यायपालिका सर्वोच्च है।

हमारी संवैधानिक व्यवस्था की शाखा, विधायिका जैसी अन्य शाखाओं के रूप में, आम जनता सहित कार्यपालिका को न्यायपालिका के आदेशों और प्रशासनिक तरीकों के साथ शामिल नहीं किया जा सकता है। के रूप में

ऐसी न्यायपालिका विशुद्ध रूप से एक स्वतंत्र निकाय है, इसलिए इसका लाभ उठाते हुए कई न्यायाधीश न्यायपालिका की छवि को धूमिल कर रहे हैं।

अपने व्यक्तिगत लाभ।

9. मिस्टर जस्टिस "... एम. के".. ने सार्वजनिक परिसरों में विशेष रूप से अपने अदालत कक्ष के परिसर में अपनी लॉ इंटर्न सुश्री के साथ हिरासत में बलात्कार किया था। डी. ", जो एक पीड़ित है और अब एक भारतीय उच्च सुसंस्कृत महिला के रूप में समाज के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबंधित है, यह कानूनी क्षेत्र में उसके वाहक को भी खराब करता है और सबसे अधिक उक्त न्यायाधीश द्वारा पैदा हुए बच्चे पर कलंक लगाता है। यह एक सिद्ध मामला है लेकिन न्याय "। एस. के. के. मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गलती करने वाले न्यायाधीश को बचाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए, श्री न्यायमूर्ति "। एस. के. के. का प्रशासन टुकड़ों में गिर गया है और नैतिक मानकों में अपूरणीय गिरावट आई है।

10. मिस्टर जस्टिस "। वी. डी. ". (सेवानिवृत्त) ने प्रतिष्ठित प्राप्त करने के लिए फर्जी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे।

मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहते हुए अपराध तब साबित हुआ जब वे मद्रास उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश थे, हालांकि, मुख्य न्यायाधीश श्री एस. के. के. ने अपने प्रशासन का दुरुपयोग किया।

और गलती करने वाले न्यायाधीश की तब तक रक्षा करके न्यायिक शक्तियाँ जब तक कि वह

सेवानिवृत्ति। यह भी एक सिद्ध मामला है जो निहित स्वार्थ का संकेत देता है

ब्याज।

पी.

11. शुरू में मैंने मद्रास शहर के समक्ष एक लिखित शिकायत दर्ज कराई।

लगभग एक महीना पहले 13 न्यायाधीशों के खिलाफ पुलिस आयुक्त

उच्चतम न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मिलकर

न्यायाधीशों, इस समूह में से श्री न्यायमूर्ति "। ई. के. 'का अर्थ है' कप्तान 'या

" अभियुक्त न्यायाधीशों की 'टीम' का भाला सिर। आरोप यह है कि

कि मेरी शिकायत में उल्लिखित सभी न्यायाधीशों ने मुझे नाराज कर दिया था

सार्वजनिक परिसरों में लगातार और लगातार आठ साल तक

लेकिन उक्त जांच अभी भी पुलिस आयुक्त के पास लंबित है

आवश्यक कार्रवाई के लिए।

12. मिस्टर जस्टिस "। के. एस. "(सेवानिवृत्त) श्री जस्टिस के पिता

एस. एम. के. ने मद्रास के सामने एक कार्यालय स्थापित किया है।

उसके पूर्व न्यायाधीश होने के परिणामस्वरूप फलदायी आदेश और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अच्छा प्रभाव डालना; यह भी एक

साबित मामला पूरी न्यायपालिका को ज्ञात है, अधिवक्ताओं के अलावा

इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, शुरू करने के लिए सबसे शीर्ष छवि को सहेजने के लिए आवश्यक कदम

न्यायपालिका। इस आशय का मेरा हार्दिक अनुरोध भी सभी के लिए है।

उन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं जो हमारे ऊपर आई हैं महान राष्ट्र एक महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायपालिका एक

?

शाश्वतता के लिए बेदाग प्रतिष्ठा "।

12. यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि वर्ष 2017 की शुरुआत में, श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन के स्थानांतरण का मुद्दा कलकत्ता उच्च न्यायालय में मद्रास उच्च न्यायालय ने सजीव सार्वजनिक बहस को जन्म दिया था। इस मोड़ पर उनका रवैया कहीं अधिक आक्रामक हो गया।

अब तक की तुलना में। उनके आक्षेप अब अधिक स्पष्ट हो गए थे, उनका प्रमुख ध्यान अपने सहयोगी मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर था।

न्यायालय (वर्तमान और पूर्व), और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जिनका मद्रास उच्च न्यायालय के साथ संबंध था, संभवतः इस विश्वास के तहत कि वे उनके क्लेशों के लिए जिम्मेदार थे। इस सूची में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीशों सहित) भी शामिल थे, जिनके पास एक

न्यायमूर्ति कर्णन से जुड़े मामलों से निपटने का अवसर। आरोपों की सामग्री और प्रकृति को समझने के लिए इनमें से कुछ संचारों को विस्तार से बताना आवश्यक है।

जे

आरई में, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

सी.

13. उपरोक्त संदर्भ में, पहले तीन का संदर्भ दिया जा सकता है।

दिनांकित संचार 27.1.2017। इनमें से पहला संदेश श्री जस्टिस को संबोधित था। एम. एम. एस. ", मद्रास के एक न्यायाधीश उच्च न्यायालय। पत्र की सामग्री से संकेत मिलता है कि संबंधित न्यायाधीश ने श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन को मदुरै पीठ में न्यायाधीशों द्वारा आयोजित साप्ताहिक बुधवार-रात के रात्रिभोज में आमंत्रित किया था। यह आरोप लगाया गया था कि हालांकि

नियत समय रात 8 बजे का था, क्योंकि वह रात्रिभोज स्थल पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए श्री जस्टिस ने उन्हें उनके टेलीफोन पर बुलाया। एम. एम. एस. ", और उनसे अनुरोध किया गया कि रात्रिभोज स्थल पर न्यायाधीश उनका (न्यायमूर्ति कर्णन) इंतजार कर रहे हैं, और वे अपना रात्रिभोज तभी शुरू करेंगे, जब वे

उसका आगमन। यह आरोप लगाया गया था कि वह (न्यायमूर्ति कर्णन) इसके तुरंत बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उपरोक्त पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि पहुंचने पर

आयोजन स्थल पर, उन्होंने देखा कि अधिकांश न्यायाधीशों ने पहले ही अपना भोजन कर लिया था, जबकि बाकी ने अपना भोजन शुरू कर दिया था। यह न्यायमूर्ति कर्णन का दावा था कि उन्हें केवल परेशान करने के लिए आमंत्रित किया गया था

उसे रैगिंग करते हुए और उसका उपहास करते हुए। चूंकि उपरोक्त कार्य थे सार्वजनिक स्थान पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया कृत्य, जस्टिस कर्णन

अपने उपरोक्त पत्र में लिखा है कि उन्होंने अपने न्यायिक अधिकार को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखा है संबंधित न्यायाधीशों के खिलाफ स्वतः कार्रवाई करने की शक्ति, और इस प्रकार

मोटू, उनके अभियोजन के लिए। तत्काल पत्र की एक प्रति का समर्थन भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री और मुख्य न्यायाधीश को किया गया

भारत से।

14. दूसरा पत्र भी 27.1.2017 का था, जिसे श्री को संबोधित किया गया था

न्यायमूर्ति ". ए. ए".. (सेवानिवृत्त)। तत्काल पत्र में उन्होंने न्यायमूर्ति पर आरोप लगाया

‘ ...... ए. ए. "और श्रीमती जस्टिस"। ए. जे. "उनके साथ उनकी भूमिका के लिए

अन्य न्यायाधीश, सामाजिक रूप से उनका (न्यायमूर्ति कर्णन) बहिष्कार करने और रैगिंग के लिए

उसे। यह बताया गया कि उन्होंने उक्त न्यायाधीशों के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी और

अनुसूचित जनजातियाँ। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि उक्त शिकायत की प्रतियां,

भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को भेजा गया था। श्री जस्टिस ". ए. ए".. और श्रीमती जस्टिस के खिलाफ स्पष्ट आक्षेप

" ...... ए. जे. "यह था कि उन्होंने अवैध संबंध विकसित किए थे, क्योंकि,

वे पति-पत्नी के रूप में व्यवहार कर रहे थे। यह भी आरोप लगाया गया था कि श्रीमती जस्टिस की बड़ी बेटी "। ए. जे. "ने आत्महत्या कर ली थी

जहर का सेवन, केवल उसके अपमान से बचने के लिए, कारण पर

श्री जस्टिस ". ए. ए".. और उनकी माँ के बीच संबंधों के बारे में

श्रीमती जस्टिस ". ए. जे. ". उपरोक्त दूसरे पत्र दिनांक 27.1.2017 में,

न्यायमूर्ति कर्णन ने आरोप लगाया कि उपरोक्त न्यायाधीश आरोपित हैं

भारतीय दंड संहिता की धारा306 के तहत, अन्य न्यायाधीशों के साथ,

उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करना। तत्काल पत्र में न्यायमूर्ति कर्णन ने उपरोक्त दो न्यायाधीशों पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया मद्रास उच्च न्यायालय के छह अन्य नामित वर्तमान न्यायाधीशों के साथ,

उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि उनके निधन के बाद धार्मिक समारोहों के संचालन में न्यायमूर्ति कर्णन को सहायता न दी जाए।

उसके पिता।

15. तीसरा पत्र भी 27.1.2017 दिनांकित था, जिसे न्यायमूर्ति कर्णन ने मद्रास उच्च न्यायालय के महापंजीयक को संबोधित किया था। यह था।

इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने (न्यायमूर्ति कर्णन) पहले ही शिकायत दर्ज करा दी थी

श्री न्याय के खिलाफ "। एस. एन. ", जिन्होंने दो रखैलियों को बनाए रखा था। अर्थात्, श्रीमती ". जे. (एम) "... और श्रीमती". आर. एस. "यह भी आरोप लगाया गया था, कि इस अवैध गठबंधन से संबंधित तथ्यात्मक स्थिति को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाया गया था। दिनांक 27.1.2017 के तीसरे संचार के माध्यम से, न्यायमूर्ति कर्णन ने इसके चरण के बारे में भी पूछताछ की थी।

जाँच, मामले की।

16. फरवरी, 2017 में न्यायमूर्ति कर्णन ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में कार्यभार संभाला। कलकत्ता से न्यायमूर्ति कर्णन ने एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतियों के साथ भारत के प्रधान मंत्री को दिनांकित पत्र,

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय के महापंजीयक। नियुक्ति प्रणाली का उपहास करने के अलावा

(उनके अनुसार) 1990 से उच्च जातियों के पक्ष में रहने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय पर उन्होंने निम्नलिखित रुख अपनायाः

" महामहिम, भारत के राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने अपना वैध दृष्टिकोण दिया है कि न्यायपालिका के लिए पारदर्शिता और स्पष्टता सर्वोपरि है। तब भी

कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके पर गोपनीयता बनाए हुए है, क्योंकि प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों में न्यायाधीशों की नियुक्ति विकसित हो रही है, जहां अवांछित चीजें हैं। वास्तव में एक अदालत के भीतर सुंदर महिलाओं को लुभाना, भारी शराब का सेवन, बड़े पैमाने पर धन का अधिग्रहण, जालसाजी और घोर दुराचार के अन्य रूपों की तरह हो रहा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं बल्कि सीधे आरोप लगा रहा हूं जिसके लिए मैं तैयार हूं।

किसी भी समय टकराव के लिए खड़ा होना। आरई में, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन [जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

17. न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा लंबे समय से लगाए गए अनुचित आरोपों को देखने के बाद, प्रथम दृष्टया यह महसूस किया गया कि बड़ी संख्या में नामित न्यायाधीशों और सामान्य रूप से न्यायपालिका के प्रति उनका आचरण,

इसने विशेष रूप से संबंधित लोगों और समग्र रूप से न्यायपालिका की छवि को गंभीर रूप से धूमिल और धूमिल किया था। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि

अवमानना की। प्रशासनिक पक्ष पर, पूरी सामग्री ऊपर निर्दिष्ट, भारत के महान्यायवादी को सौंपा गया था। उनसे न्यायिक पक्ष से इस मामले में अदालत की सहायता करने का भी अनुरोध किया गया था।

8.2.2017 पर, पीठ ने पहला न्यायिक आदेश पारित किया:

" 1. श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन को नोटिस जारी करें, जो अब वापस किया जा सकता है।

13.02.2017 .

2. रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति और नोटिस जारी करते समय जिन पत्रों पर ध्यान दिया गया है, वे दिन के दौरान न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन को दिए जाएं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के महापंजीयक।
3. श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन, उनके द्वारा धारण किए गए पद को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक कार्य को संभालने से तुरंत परहेज करेंगे, जो उन्हें सौंपा गया हो। उसे अपने कब्जे में मौजूद सभी न्यायिक और प्रशासनिक फाइलों को वापस करने का भी निर्देश दिया जाता है।

उच्च न्यायालय के महापंजीयक को तुरंत।

4. श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

सुनवाई की अगली तारीख को, कारण दिखाने के लिए। 5. विद्वान महान्यायवादी ने आज सुनवाई के 2 पाठ्यक्रम के दौरान हमारी सहायता की है। हम.

उससे आगे की कार्यवाही के दौरान हमारी सहायता करने का अनुरोध करें।

मामले में "।

18. श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन ने दिनांक 1 (ऊपर निकाले गए) के आदेश के जवाब में इसके महापंजीयक को एक पत्र लिखा।

10.2.2017 पर अदालत। दीक्षा पर उन्होंने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए: उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही:

" उपर्युक्त स्वतः संज्ञान याचिका में यह उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ विचारणीय नहीं है, आगे स्वतः संज्ञान याचिका

मेरे खिलाफ अवमानना आदेश पारित किया गया, क्योंकि मैंने भेजा है

विभिन्न सरकारों को ज्ञापन। उच्चाधिकारियों के बारे में

एक शीर्ष अदालत की रिपोर्ट

[2017] 9 एस सी आर।

न्यायिक न्यायालयों में होने वाली अनियमितताएँ और अवैधताएँ। विशेष रूप से इस तरह की बड़ी अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए मैं एक जिम्मेदार न्यायाधीश भी हूं। भ्रष्टाचार और कदाचार। मैंने व्यापक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं।

संबंधित न्यायालयों के साथ होने वाली अनैतिक प्रथाओं का।

मुझसे कोई स्पष्टीकरण प्राप्त करने से पहले, मैं यह बताना चाहता हूं कि

अदालतों के पास बैठक के खिलाफ सजा लागू करने की कोई शक्ति नहीं है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यह उक्त आदेश इसके अनुरूप नहीं है -

तर्क, इसलिए यह निष्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। इस आदेश की विशेषता स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उच्च जाति के न्यायाधीश ले रहे हैं

एक एससी/एसटी न्यायाधीश (दलित) के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण इरादे से उससे छुटकारा पाने के लिए। इसलिए 8.2.2017 दिनांकित स्वतः संज्ञान अवमानना आदेश कानून के तहत टिकाऊ नहीं है। 15.2.2016 पर मैंने मद्रास उच्च न्यायालय परिसर के सामने एक बयान की घोषणा की जो

प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भाग लिया जिसमें

मेरा महत्वपूर्ण कथन यह था कि मिस्टर जस्टिस "। एसकेके।

उपरोक्त न्यायालय में सभी भ्रष्टाचार की जड़ है। अपनी घोषणा की पुष्टि करने के लिए, मैंने किसी भी घोषणा का विरोध करने की पेशकश भी की

वह मेरे खिलाफ अवमानना का आदेश दे सकता है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि वह तथ्यों का सामना करने से सावधान थे। अब, एक साल से अधिक समय तक इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप रहने के बाद, या एक कहावत के रूप में जो कहती हैः

" धूल जैसे-जैसे जम गई ", उन्होंने खुद इस मुद्दे को उठाया

सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए एक उम्मीदवार के रूप में। अब मैं उन्हें इस 11 वें घंटे में भी चुनौती देता हूं कि वे खुद को बेदाग साबित करें। न्यायाधीश ताकि वह उच्चतम न्यायालय के रूप में पदोन्नति के लिए योग्य हो सके

न्यायाधीश।

इसके अलावा, 1 ने हाल ही में एक आरोप भी लगाया कि 20 थे

मद्रास उच्च न्यायालय के भ्रष्ट न्यायाधीश और वह माननीय न्यायाधीश "। के. के. "नहीं है। मुझे, यहां तक कि इस आरोप को भी नजरअंदाज कर दिया गया था, हालांकि मेरी शिकायत अभी भी फाइल में है। यह देखा गया है कि 7

ऊपर उल्लिखित न्यायाधीश मेरे खिलाफ अवमानना मामले के लिए तैयार हैं, संभवतः न्यायमूर्ति श्री "46 के लिए रास्ता साफ करने के लिए। एस. के. के. "

ऊँचाई; कृपया इसे "घोड़े के बोल्ट होने के बाद अस्तबल को बंद करने" का मामला न होने दें। उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान अवमानना आदेश

मैं एक दलित न्यायाधीश हूं और मेरे न्यायिक और प्रशासनिक कार्य पर रोक लगाना अनैतिक है और एससी/एसटी अत्याचारों के खिलाफ है

एक्ट करें। यह निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस मुद्दे को संसद के सदन को भेजना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय होगा। 15.2.2016 पर।

1 आरई में, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन [जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

मेरी घोषणा में यह भी शामिल किया गया है कि माननीय न्यायमूर्ति श्री।

जे. एस. के. "और श्रीमती जस्टिस"। आर. बी. ".. ने मेरे खिलाफ एक समान कठोर आदेश पारित किया, इसलिए मैं चेन्नई के पुलिस आयुक्त को दोनों उल्लिखित माननीय न्यायाधीशों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देने के लिए विवश हूं। इसलिए, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश स्पष्ट रूप से वही पूर्वाग्रह सहन कर रहे हैं जो

अतीत में एक ही आदेश पारित करके।

इसलिए मेरा गहरा अनुरोध है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद स्वतः संज्ञान अवमानना की सुनवाई की जाए। इस बीच मेरे प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य को बहाल किया जा सका। मेरा मुख्य तर्क केवल भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। मद्रास उच्च न्यायालय, और पवित्रता और गरिमा को खराब करने के लिए नहीं

अदालत से।

जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अपमान करके संविधान के 14 और 21 के तारांकित अनुच्छेदों को प्रभावित करते हैं। मैंने भ्रष्ट न्यायाधीशों की एक सूची जारी की जिसमें एक जांच अनिवार्य है, जैसे कि सुओ स्वतः अवमानना याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है। का आदेश

स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका में सर्वोच्च न्यायालय गलत है और जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से पारित किया गया है। इसलिए, इन कार्यवाहियों को संसद को भेजा जा सकता है, जिसमें मैं भ्रष्टाचार की उच्च दर को स्थापित करूंगा। मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायपालिका। उक्त आदेश संविधान के अनुच्छेद 219 का भी उल्लंघन करता है क्योंकि इसमें स्पष्ट दोष है।

क्रम में होगा। इसलिए, मैं माननीय न्यायाधीशों से अनुरोध करता हूं कि वे भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद मामले की सुनवाई करें, लेकिन यदि इसे तत्काल माना जाए तो मामले को संसद में भेज दें। यह

यह मेरा विनम्र और तत्काल समर्पण है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित समय नहीं दिया था जो अत्यधिक अनियमित है।

श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन के उपरोक्त पत्र का अवलोकन बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्होंने बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाए थे, जिन्हें उन्होंने बरकरार रखा, वे सही थे। वह भी।

स्वीकार किया, कि उन्होंने मीडिया को संबोधित किया था, इस अदालत के बाद

उन्हें नोटिस (8.2.2017 पर), जिसमें उन्होंने आरोपों की पुष्टि की

इसा

उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के 20 नामित न्यायाधीशों के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने प्रेस के सामने यह भी घोषणा की कि उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट न्यायाधीशों की सूची में सबसे ऊपर थे। उन्होंने चेन्नई के पुलिस आयुक्त को एक निर्देश जारी करते हुए यह भी पुष्टि की,

:

उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों के खिलाफ मामला दर्ज करना (श्री न्यायमूर्ति " ...... जे. एस. के. "और श्रीमती जस्टिस"। आर. बी.), उनके द्वारा पारित न्यायिक आदेश के संदर्भ में।

19. श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन को विधिवत नोटिस दिया गया था

13.2.2017 के लिए सुओ-मोटू अवमानना याचिका। उन्हें पहले के आदेश दिनांक 8.2.2017 के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया था। वह.

अनुपस्थित और बिना प्रतिनिधित्व के रहने का फैसला किया। इसलिए यह था कि

दूसरा न्यायिक आदेश 13.2.2017 पर पारित किया गया था। उपरोक्त आदेश ने पहले आदेश (दिनांक 8.2.2017) द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों की पुष्टि की। पीठ ने न्यायमूर्ति कर्णन के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने के बजाय,

निर्देश के अनुसार उपस्थिति दर्ज नहीं करने के लिए (उचित सेवा के बावजूद), न्यायमूर्ति कर्णन को सुनवाई की अगली तारीख 10.3.2017 पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई। 13.2.2017 दिनांकित आदेश का पाठ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन को विधिवत सेवा प्रदान की गई है।

प्रस्ताव पीठ का आदेश दिनांक 08.02.2017। श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन द्वारा सचिव को संबोधित दिनांक 1 का एक पत्र

इस न्यायालय के जनरल को इस की रजिस्ट्री में प्राप्त किया गया है।

अदालत। उपरोक्त संचार के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका लिखा है। हस्ताक्षर किए। श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन का उपरोक्त पत्र लिया गया है।

रिकॉर्ड में।

2. उचित नोटिस के बावजूद, न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन पेश नहीं हुए हैं। श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन ने किसी को भी प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत नहीं किया है।

आज उसे। किसी भी मामले में, आज किसी के पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, जिसने उनका प्रतिनिधित्व किया है। हम उनकी गैर-उपस्थिति के कारणों से अवगत नहीं हैं। इसलिए हम आगे बढ़ने से बचते हैं।

3. सुनवाई के लिए 10.03.2017 पर सुबह 10.30 पर पोस्ट करें। श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। हम एतद्वारा यह भी निर्देश देते हैं कि इस मामले में 08.02.2017 पर पारित अंतरिम आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।

4. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कुछ वकील अपने दम पर उपस्थित हुए। हमने उनसे पूछा कि क्या उन्हें श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया था, और उनके पास इस अधिकार का अधिकार था -

उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील। उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था। ये

विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने आरई में अभियोग दायर करने का प्रस्ताव रखा, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

किसी संगठन की ओर से आवेदन। प्रलोभन के लिए मौखिक प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जाता है।

5. चूँकि अवमानना की कार्यवाही अदालत और कथित अवमानक के बीच सख्ती से एक मामला है, कोई भी व्यक्ति जो उपस्थिति दर्ज करता है

आर

और भविष्य में इस मामले की कार्यवाही को बाधित करता है, यह समझें कि उसके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई की जा सकती है। हमें बस इतना कहना है कि किसी को भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए।

यह मामला, उचित सहमति और प्राधिकरण के बिना।

6. रजिस्ट्री श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन को तत्काल आदेश के बारे में उसी तरह बताएगी जैसे उन्हें सूचित किया गया था

पिछला आदेश "।

20. आई. डी. 1 पर न्यायमूर्ति कर्णन ने इस न्यायालय के महासचिव को एक और पत्र लिखा। और महासचिव के माध्यम से,

अवमानना कार्यवाही से निपटने वाली पीठ के सदस्य। में।

तत्काल पत्र में उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि वह अपनी न्यायिक व्यवस्था को बहाल करे और

प्रशासनिक कार्य, क्योंकि वे जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले थे। उन्होंने अवमानना कार्यवाही को आगे बढ़ाने में इस न्यायालय के साथ सहयोग करने का भी बीड़ा उठाया।

उसके खिलाफ शुरू किया। उपरोक्त दिनांकित संचार का संक्षिप्त पाठ

13.2.2017 , इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" मेरे माननीय स्वामी, कृपया मेरा प्रशासनिक और न्यायिक कार्य फिर से शुरू करें।

तुरंत काम करें क्योंकि मेरी सेवानिवृत्ति निकट है। मैं निश्चित रूप से अवमानना की कार्यवाही में सहयोग करूंगा; कृपया सभी को प्रसारित करें। संबंधित माननीय न्यायाधीश और बाध्य।

न्यायमूर्ति कर्णन ने उन्हें जारी किए गए कारण बताएँ नोटिस के लिए एक अलग आईडी1 दिनांकित पत्र को भी संबोधित किया, जिसे उनका स्पष्टीकरण माना जाता है।

उसी का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

भारत की आम जनता।

(2) मैं हमेशा की तरह दोहराता हूं कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान मैंने जिन न्यायालयों में सेवा की और अभी भी सेवा कर रहा हूं, उनमें भ्रष्टाचार की उच्च दर के बारे में,

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अलावा। मैं अपने प्रयासों को नहीं रोकूंगा और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कि हर गलत काम को उखाड़ फेंका नहीं जाता।

(3) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुस्लिमों जैसे अल्पसंख्यक समुदायों से पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 9 एस सी आर।

ईसाई, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और सबसे पिछड़े समुदायों से लेकर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय तक भले ही न्यायाधीशों की कुल संख्या लगभग 1100 है, लेकिन मेरे सहित कुछ ही लोग शांति के न्यायाधीश के पद पर हैं।

(4) इसलिए, मैं माननीय उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम से अनुसूचित जाति के लगभग 400 उम्मीदवारों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध करता हूं।

अनुसूचित जनजाति और सबसे पिछड़े सहित अल्पसंख्यकों की

वर्ग ताकि न्याय एक तटस्थ रुख पर प्रबल हो और कोई भी पक्षपाती न हो और किसी को लाभ न हो। शक्ति का संतुलन

अगर दुर्भाग्य से उच्च जाति के न्यायाधीशों के साथ केंद्रित है जिसके परिणामस्वरूप भारत में अब तक का सबसे खराब भ्रष्ट परिदृश्य देखा गया है

1947 में स्वतंत्रता। मैं, न्यायपालिका के एक सेवारत न्यायाधीश के रूप में भ्रष्ट न्यायाधीशों द्वारा न्यायपालिका के पतन को बर्दाश्त नहीं कर सकता।

और इस संबंध में मैंने वर्षों से विभिन्न न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार को दर्ज किया है। (5) मिस्टर जस्टिस "। एन. के. ", मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने मुझे अपने जूते से लात मारी और चालाकी से मेरे नाम का टैग हटा दिया।

एक सार्वजनिक समारोह में अपनी सीट पर और मैंने तुरंत इस मामले की सूचना उच्चतम न्यायालय को अध्यक्ष को दी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग। यह घटना

एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश से आने वाले पूर्वाग्रह की स्मैक्स और है

भारतीय अत्याचार अधिनियम के अनुसार भ्रष्टाचार का सबसे बुरा रूप

संविधान। यह शिकायत लगभग 4 साल से अदालत में लंबित है। इसलिए, मैं अपने सभी आरोपों की व्यापक जांच की मांग कर रहा हूं।

(6) मिस्टर जस्टिस ". एस. एम. के. ". ने अपनी प्रशिक्षु सुश्री". डी ".. के साथ हिरासत में बलात्कार किया है और इसके परिणामस्वरूप

उसके कायरतापूर्ण अपराध से वह गर्भवती हुई और एक पुरुष बच्चे को जन्म दिया। सुश्री ". डी". और बालक दोनों जीवित हैं। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किए गए इस नृशंस अपराध का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आरोप लगाया है, तो मामले की अधिक जांच क्यों नहीं की जा सकती है।

पेशेवर जांचकर्ता? मद्रास उच्च न्यायालय के परिसर से आने वाली इस घटना के बारे में अब आम जनता को पता है। है।

आम जनता का मानना है कि न्यायाधीश कानून से ऊपर हैं?

जैसा कि कोई भी आसानी से समझ सकता है, ये वास्तविक कारण हैं कि मैं अपने सभी आरोपों की व्यापक समीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

और माना नहीं जा सकता-"एक खराब करने वाला खेल"। मेरे सभी प्रयास सबसे अधिक हैं।

यह सर्वोपरि और अनिवार्य है क्योंकि यह न्यायालयों की पवित्रता और गरिमा को बनाए रखने के लिए है। न्यायमूर्ति कर्णन के उपरोक्त जवाब के अवलोकन से पता चलता है कि उनके

भ्रष्टाचार की उच्च दर के बारे में स्पष्ट और दृढ़ दावा

उन्होंने 10.3.2017 पर भी उपस्थिति दर्ज नहीं करने का फैसला किया। इसे खरीदने के लिए श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन की उपस्थिति में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित पारित किया:

10.3.2017 पर आदेश दें:

" 1. इस याचिका का नोटिस विधिवत दिया गया है। सेवा के बावजूद,

जहाँ इस न्यायालय में श्री न्यायमूर्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य थी, वहाँ उन्होंने न तो उपस्थिति दर्ज की है।

व्यक्ति, न ही परामर्श के माध्यम से।

उनके द्वारा कुछ नामित न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए गए आरोप। द. उपरोक्त फैक्स संदेश, दिनांक 08.03.2017, को या तो अवमानना याचिका पर श्री न्यायमूर्ति C.S.Karnan की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं माना जा सकता है,

या उसे दिए गए नोटिस के लिए।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, तलाश करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है

जमानती जारी करके श्री जस्टिस C.S.Karnan की उपस्थिति

आदेश देते हैं। तदनुसार आदेश दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की संतुष्टि के लिए, व्यक्तिगत बांड की प्रकृति में, Rs.10,000/- (दस हजार रुपये) की राशि में जमानती वारंट जारी किए जाएं।

श्री न्यायमूर्ति की उपस्थिति। C.S.Karnan, इस न्यायालय में, पर

31.03.2017 , 10.30 ए. एम. पर

4. हम सराहना करेंगे यदि उपरोक्त जमानती वारंट हैं,

श्री जस्टिस C.S.Karnan पर सेवा की, के महानिदेशक द्वारा

पुलिस, पश्चिम बंगाल।

5. सुनवाई के लिए 31.03.2017,10.30 AM पर पोस्ट करें।

22. उसी दिन 10.3.2017 का तीसरा न्यायिक आदेश था

पारित, श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन ने कथित रूप से स्वतः संज्ञान असाधारण मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए (संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत)

भारत सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के साथ पठित), 10.3.2017 दिनांकित आदेश पारित किया। उपरोक्त क्रम का प्रासंगिक भाग है -

नीचे निकाला गया हैः

" जैसा कि कानून को पता है, कोई भी अवमानना या तो दीवानी या आपराधिक नहीं हो सकती है।

न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 2 (सी), 12 और 14 के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत उच्च न्यायालय के किसी मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन पूर्व-कल्पित पूर्वाग्रहपूर्ण धारणा के कारण अभियुक्त व्यक्तियों ने न्याय की सभी तोपों को नष्ट कर दिया है

उपरोक्त गैरकानूनी, अवैध और असंवैधानिक अवमानना कार्यवाही केवल इस दृष्टिकोण से शुरू की गई कि इस न्यायालय के अनुसूचित जाति से संबंधित एक वर्तमान न्यायाधीश को किसी तरह दंडित किया जाए समुदाय।

2. यह भी एक सर्वविदित कारक है जो केवल महाभियोग का प्रस्ताव है

न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत उचित जांच के बाद संसद के समक्ष उच्च न्यायपालिका के किसी वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

3. यह न्यायिक जानकारी के भीतर अच्छी तरह से पहला प्रयास किया गया था

के उच्च न्यायालय से रंगीन स्थानांतरण में सर्वोच्च न्यायालय

मद्रास में कलकत्ता में उच्च न्यायालय का न्यायिक कार्य।
4. यह भी एक खुला रहस्य है कि इससे पहले एक कठोर शपथ पत्र दायर किया गया था।

अधिवक्ता शांति भूषण और प्रशांत द्वारा सर्वोच्च न्यायालय

भूषण ने इसी तरह के अवमानना मामले में कई लोगों को छुआ

उच्चतम न्यायालय के वर्तमान और पूर्व न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप अब वर्षों से उच्चतम न्यायालय के ठंडे बस्ते में लंबित हैं।

बिना किसी कार्रवाई के।

5. यह न्यायिक जानकारी के भीतर भी है कि उपयुक्त कार्यकारी, विधायी और न्यायिक प्राधिकरणों को सभी संचार, मसौदा केवल कानूनी उद्यम की अनुमति है जो किसी भी तरह से आमंत्रित नहीं करता है।

6. एक अन्य निर्णायक मैट्रिक्स यह है कि निम्नलिखित 13 व्यक्तियों में से कोई भी नहीं है। इसके विरुद्ध किसी भी शिकायत या बचाव को प्राथमिकता दी है, जबकि

अभियुक्त व्यक्तियों ने खुद को प्रोटोकॉल के रूप में लिया है

निम्नलिखित व्यक्तियों के आरोपों पर संरक्षकः

:

आरई में, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन [जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

" 1. मिस्टर जस्टिस "। एसकेके।

29 .

2. मिस्टर जस्टिस "। एसएमके.

79 .

3. मिस्टर जस्टिस "। V.R.S.M.. "9. ▸

5. मिस्टर जस्टिस "। आर. एस. आर. "
6. मिस्टर जस्टिस "। आर. के. ए. ";

7. मिस्टर जस्टिस "। टी. एस. टी. ";
8. मिस्टर जस्टिस ". एम. वाई. आई.

9. मिस्टर जस्टिस "। आई. के. ";

10. मिस्टर जस्टिस ". ए. के.

11. मिस्टर जस्टिस "। ई. डी. आर. ";

12. मिस्टर जस्टिस "। के. एन. बी

.

13. मिस्टर जस्टिस ". ए. ए".;
14. श्रीमती जस्टिस ". ए. जे. ";>

15. मिस्टर जस्टिस "। वी. डी. वी. डी. ";

16. मिस्टर जस्टिस "एम. एम. एस".।

17 मिस्टर जस्टिस ". एन. के.

18. मिस्टर जस्टिस "। एन. एन. ";

19. मिस्टर जस्टिस "। टी. आर. ";

20. मिस्टर जस्टिस "... एस. एस"..।
21. श्री ". एच"., निजी सचिव-सह-पंजीयक;

22. श्री ". पी. के. "., पंजीयक; और

23. श्री "... एस. पी"., अधिवक्ता और अध्यक्ष,

तमिलनाडु अधिवक्ता संघ।

XXX

XXX

XXX

नतीजतन, मैं केंद्रीय जांच ब्यूरो को पंजीकरण करने का निर्देश देता हूं। दुरुपयोग को रोकने के लिए धारा 482 Cr.P.C के साथ पठित अनुच्छेद 226 के तहत उपयुक्त न्यायालय के समक्ष जांच करें और एक रिपोर्ट दायर करें।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के उपयुक्त आपराधिक प्रावधानों के तहत इस माननीय न्यायालय की मेरी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना। 1989 और अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अन्य दंडात्मक प्रावधान और मैं लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को निर्देश देता हूं कि वे न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत उचित जांच के लिए मामले के पूरे तथ्यों को अध्यक्ष के समक्ष रखें और इसके परिणामस्वरूप मैं महामहिम भारत के राष्ट्रपति से अनुरोध करता हूं कि वे अवैध रूप से जारी जमानती वारंट को वापस लें

शीर्ष अदालत की रिपोर्ट

[2017] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10.3.2017 पर और गैर-कार्य आवंटन को हटा दिया गया

इस माननीय न्यायालय के समक्ष। आज 10 मार्च, 2017 को मेरे द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित। "

उपरोक्त स्वतः संज्ञान आदेश का इस न्यायालय में समर्थन किया गया था। यह राज्यसभा सचिवालय (विधायी अनुभाग) को अनुमोदित किया गया था,

इसके बाद, राज्य सभा सचिवालय (विधायी अनुभाग) ने संबोधित किया

इस न्यायालय को पत्रः

" राज्य सभा सचिव

(विधायी खंड)

विषयः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत स्वतः संज्ञान विशेष मूल अधिकार क्षेत्र-श्री न्यायमूर्ति सी. एस.

कर्णन, न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय।

उपर्युक्त आई. एन. आर. ई. पर संचार की एक प्रति, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

10 मार्च, 2017 का एक आदेश पारित किया गया

श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन, न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय

सुओ-मोटु डब्ल्यू. पी. (आपराधिक) नहीं। 1 2017 को इसके साथ भेजा गया है। आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीश

भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायालय (में उल्लिखित नाम)

आदेश), भारत के महान्यायवादी के साथ स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका (सी) सं। 1 2017 के दिनांक 8.2.2017 ने कॉल किया है

विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए 10.3.2017 पर उनकी उपस्थिति के लिए और

अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया कि राज्य सभा के महासचिव

न्यायाधीशों (जांच) के तहत उचित जांच के लिए मामले के पूरे तथ्यों को माननीय सभापति, राज्य सभा के समक्ष रखें। अधिनियम, 1968। श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन ने मामले को अनुपालन और रिपोर्टिंग के लिए 31.3.2017 पर पोस्ट किया है।

2. इस संबंध में, यह कहा गया है कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के प्रावधान केवल तभी लागू होते हैं जब संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 (1) के तहत एक ठोस प्रस्ताव बैठक की आवश्यकता होती है। माननीय सभापति, राज्यसभा कुछ भी नहीं ले सकती है

इस स्तर पर इस संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी क्योंकि न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा वांछित कार्रवाई करने पर विचार करने के लिए उनके समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, प्रथा और परंपरा के अनुसार, माननीय सभापति, राज्य सभा या महासचिव, राज्य सभा का जवाब नहीं है

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

अदालतों से प्राप्त नोटिस/आदेश और ऐसे सभी

संचार कानून और न्याय मंत्रालय को भेजे जाते हैं

संबंधित न्यायालय को सही संवैधानिक/प्रावधान के बारे में अवगत कराने के लिए

कानूनी प्रक्रिया।

3. इसलिए विधि और न्याय मंत्रालय से अनुरोध है कि कृपया

उपरोक्त मामले को देखें और श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन को सूचित करें,

न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय से संबंधित प्रक्रिया के बारे में

जाँच या जाँच समिति का गठन करना

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अधीन। ”

न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा पारित आदेश और पत्र का अवलोकन

राज्यसभा सचिवालय (विधायी अनुभाग) द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुमोदित, नाम से न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने में उनके कार्यों की निरंतरता की पुष्टि करता है। उपरोक्त संचार

यह भी प्रदर्शित करें कि वह भ्रष्टाचार के आरोपों को प्रचारित करना चाहते थे,

अपने सहयोगी न्यायाधीशों के खिलाफ।

23. इस मोड़ पर, इस न्यायालय को एक बहुत ही दिलचस्प बात मिली

कलकत्ता उच्च न्यायालय के महापंजीयक से संचार। न्यायमूर्ति कर्णन ने उपरोक्त संदेश को संबोधित किया था (-दिनांकित)

14.3.2017) कलकत्ता उच्च न्यायालय के महापंजीयक को। द.

उसी को नीचे निकाला गया हैः

तिथि 14 मार्च, 2017

" को।

महापंजीयक,

उच्च न्यायालय,

कलकत्ता

आदरणीय साहब,

9.3.2017 पर श्री मैथ्यू, अधिवक्ता, उनकी प्रकोष्ठ संख्या।

9820535428 , स्वेच्छा से मेरे आवास पर आए और मुझ पर जोर दिया एक आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए जो पहले से ही मेरे नाम पर तैयार था। में

उक्त आदेश के अनुसार मुझे माननीय न्यायाधीशों को नोटिस देना आवश्यक था नाम नीचे दिया गया हैः

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति "। जे. एस. के. "और

न्यायमूर्ति श्री ". डी. एम.। ...... " , लिखे गए सुसाइड नोट के आधार पर

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा, जो मैं पूरी तरह से इनकार किया और साथ ही मेरे निजी सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिया

उक्त अधिवक्ता को मेरे आवास से बाहर भेजें। तदनुसार उन्होंने

बाहर भेजा गया। रिट याचिका की प्रति और आदेश ने सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट तैयार की

[201
7] 9 एस सी आर।

जैसा कि उल्लेख किया गया है, माननीय न्यायाधीशों को रिपोर्ट प्रस्तुत करें उपरोक्त आवश्यक जांच और उचित कार्रवाई के लिए।

उपरोक्त संचार को पंजीयक द्वारा अनुमोदित किया गया था

उच्चतम न्यायालय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के जनरल, इसके साथ घेराव। घेरों में दायर एक रिट याचिका का पाठ था

विजय कृष्ण अधिकारी का नाम, और कथित मसौदा आदेश, जिसके बारे में न्यायमूर्ति कर्णन दावा करते हैं, पर उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था।

24. जब अवमानना की कार्यवाही चल रही थी, न्यायमूर्ति कर्णन

उनके कथित संदर्भ में इस न्यायालय को नियमित रूप से संबोधित पत्र आचरण, और उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही, उन्होंने इस विषय पर मीडिया को संबोधित करना भी जारी रखा। यह बहुत प्रासंगिक है।

इस मोड़ पर, उन्होंने एक और स्वतः संज्ञान न्यायिक आदेश पारित किया (कथित रूप से, आह्वान करते हुए)

भारत के संविधान का अनुच्छेद 226, धारा 482 के साथ पढ़ा जाता है दंड प्रक्रिया संहिता), दिनांक 15.3.2017। उपरोक्त का पाठ

आदेश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" कलकत्ता में उच्च न्यायालय में

अनुच्छेद 226 को लागू करने के बाद स्वतः संज्ञान न्यायिक आदेश पारित किया गया

भारत का संविधान धारा 482, दंड प्रक्रिया संहिता के साथ पढ़ा जाता है।

वर्तमान न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन

को।

डी.

15.03.2017

निदेशक,

केंद्रीय जांच ब्यूरो,

नई दिल्ली

मैंने माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष शिकायत की है।

भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय के 20 माननीय न्यायाधीशों के विरुद्ध और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अर्थात्ः

" 1. मिस्टर जस्टिस "। एस. के. के. ";

2. मिस्टर जस्टिस "। एसएमके.

3 . मिस्टर जस्टिस "। V.R.S.M.. ";

4 . श्रीमती जस्टिस ". सी. वी"..;

5 . मिस्टर जस्टिस "। आर एस आर।

6 . मिस्टर जस्टिस ". आर. के. ए.

7. मिस्टर जस्टिस "। टी. एस. टी. ";

8. मिस्टर जस्टिस "। एम. वाई. ई.

आई.

1

आरई में, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]।

9 .

मिस्टर जस्टिस "। आई. के. ";

मिस्टर जस्टिस ". ए. के.

10 .

99 .

11 .

मिस्टर जस्टिस "। ई. डी. आर
मिस्टर जस्टिस "। के. एन. बी. ";

12 .
13 .

मिस्टर जस्टिस ". ए. ए".;

श्रीमती जस्टिस "... ए. जे. ए. जे.।

14 .

मिस्टर जस्टिस "। वी. डी. ";

15 .

मिस्टर जस्टिस। एमएमएस "।

16 .

मिस्टर जस्टिस "। एनके. एनके. ";

........17 .

जे.

18 .

मिस्टर जस्टिस "। एनएन.

मिस्टर जस्टिस "। टी. आर.

19 .

20 .

मिस्टर जस्टिस ". एस".

उक्त शिकायत की फाइल पर अभी भी जांच लंबित है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी। उक्त शिकायत में मैंने न्यायाधीशों की बेईमानी की जांच करने के लिए 10 निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है।

इन परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

मेरे न्यायिक और प्रशासनिक काम पर भी रोक लगाना, उक्त आदेश कानून के तहत टिकाऊ नहीं है क्योंकि कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय से कार्रवाई का कोई कारण नहीं बनता है और कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह से

माननीय न्यायाधीशों ने अपने न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों का दुरुपयोग किया है

शक्ति। इसके अलावा माननीय 7 न्यायाधीश जिन्होंने एक असंवैधानिक पीठ का गठन करके भारतीय संवैधानिक कानून को तोड़ने के बाद, इसलिए वे अवमानक हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है।

अपने ही न्यायालय की अवमानना। इसके अलावा माननीय न्यायाधीशों ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से मेरा अपमान किया है।

एक सार्वजनिक संस्था जो एक दलित के प्रति उत्पीड़न के बराबर है

न्यायाधीश। इस प्रकार सभी 7 माननीय न्यायाधीशों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत लाया गया है।

अत्याचार अधिनियम। इसलिए, मैंने आपको एक व्यापक जांच के लिए और संसद के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक स्वतः संज्ञान न्यायिक आदेश पारित किया है।

अब मैं अपने सुओ-मोटो के माध्यम से एक और दिशा दे रहा हूँ।

न्यायिक आदेश दिनांक 23.1.2017 पर मेरी शिकायत पर विस्तृत जांच करने और आगे की चर्चा के लिए संसद के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इसके अलावा आम तौर पर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसके खिलाफ भी शिकायत की जाती है

वह संबोधित कर सकता है, फिर उस शिकायत का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर किया जाना चाहिए

[2017] 9 एस सी आर।

गुण जो कानून की प्रक्रिया है। मेरे मामले में माननीय 7 न्यायाधीशों ने कानून की प्रक्रियाओं का पालन किए बिना और कानून को अपने हाथों में लेकर अपनी न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों को अपनी पसंद के अनुसार संचालित किया है, इसके अलावा माननीय न्यायाधीशों ने जानबूझकर माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय की अनदेखी की है, जिसमें मेरी शिकायत की जांच लंबित है। के रूप में

ऐसे माननीय न्यायाधीशों ने अनुच्छेद 219 का उल्लंघन किया है

संविधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करने के अलावा अनुच्छेद 14,21 और 19 (जी) (आई) के खिलाफ काम करता है जो प्रमुख हैं। संविधान के अनुच्छेद।

इसलिए, 23.1.2017 पर मेरी शिकायत पर जो होनी चाहिए

जनता के विश्वास और सुविधा के संतुलन को बनाए रखने के लिए गुण-दोष पर निर्णय लेना सर्वोपरि है। इसके अलावा मैं यह वचन देता हूँ कि मैं अपनी दिनांकित 23.1.2017 की शिकायत को स्थापित करने के लिए अपने पूर्ण सहयोग और समन्वय का विस्तार करूँगा और

दस्तावेजी प्रमाण जो मद्रास उच्च न्यायालय में उपलब्ध है

रजिस्ट्री। तदनुसार आदेश दिया।

1. न्याय "। जे. एस. के. "-भारत के मुख्य न्यायाधीश

2. जस्टिस ". डी. एम.

3. जस्टिस ". जे. सी".।

4. न्याय "। आर. जी.. "

5. न्याय "। एमबीएल "।

6. न्याय "। पी. सी. जी. "

7. न्याय "। के. जे. "

मेरे स्वामी, मेरी दिनांकित 23.1.2017 की शिकायत पर जो 20 न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत दर्ज की गई है। शुल्क लेते हैं। अब उक्त शिकायत का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाना है -

निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली।

इसलिए आपकी स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका सं। 1 2017 का और जमानती वारंट सहित इसके अंतरिम आदेश निष्फल और अमान्य हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे उपरोक्त संवैधानिक पीठ को रद्द करने और अपनी सामान्य न्यायिक व्यवस्था को बहाल करने का गहरा अनुरोध करता हूं।

और प्रशासनिक कार्य और बाध्य।

आ
पका।

एसडी /

(न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन) "

आरई में, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

: .

हमारे लिए पत्र की सामग्री को संक्षेप में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

ऊपर उल्लेख किया गया है। हमने इसके किसी भी हिस्से को उजागर नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि, पत्र की सामग्री यह दर्शाती है कि न्यायमूर्ति कर्णन के मन में उनके सहयोगी न्यायाधीशों के खिलाफ द्वेषपूर्ण प्रयास किया गया था।

25 ऑन. 16.3.2017 , न्यायमूर्ति कर्णन ने निम्नलिखित को संबोधित कियाः

इस पीठ के सदस्यों के लिए नगरपालिकाः

" को।

तारीखः

16.03.2017 -

1.- न्याय "... जे. एस. के. ...... " - भारत के मुख्य न्यायाधीश

2. न्याय "। डी. एम. "

3. जस्टिस ". जे. सी.

4. न्याय

66 आर. जी.

5. न्यायमूर्ति एम. बी. एल.

6. न्याय "। पी. सी. जी. "

7. न्याय "। के. जे. "

मेरे स्वामी, आपने एक असंवैधानिक पीठ का गठन किया है।

भारतीय संवैधानिक कानून को तोड़ने और एक सुओ पारित करने के बाद

सुओ-मोटु अवमानना याचिका में मेरे खिलाफ मोटु अवमानना आदेश

नहीं। 2017 का I जिसमें आपने मेरे न्यायिक और

प्रशासनिक कार्य, उक्त आदेश दुर्भावना के साथ पारित किया गया है एक दलित न्यायाधीश (स्वयं) को परेशान करने का इरादा।

मामले की तथ्यात्मक स्थिति यह है कि मैंने एक

पहले बेईमानी के लिए 20 न्यायाधीशों के खिलाफ दिनांकित 23.1.2017 की शिकायत

भारत के माननीय प्रधानमंत्री, जिनकी जाँच लंबित है।

इन परिस्थितियों में, उपर्युक्त माननीय न्यायाधीश

बचाव के लिए एक सुओ-मोटू अवमानना आदेश जारी किया है

भ्रष्ट न्यायाधीश। इस प्रकार उपरोक्त माननीय न्यायाधीश उनके साथ भी मिलीभगत की है और उनका समर्थन हासिल किया है

न्यायिक शक्ति का संचालन कार्रवाई के कारण से, अधिकार क्षेत्र से बाहर, प्रावधान से बाहर और एक गलत मंच का गठन किया।

न्यायाधीश का अर्थ है कानून का एक सम्मानित व्यक्ति जिसे सुनना होता है।

मामले के दोनों पक्ष और कानून के अनुसार आदेश पारित करते हैं। में। तत्काल मामले में माननीय न्यायाधीशों ने मामले का बचाव किया है

20 त्रुटिपूर्ण न्यायाधीशों की ओर से। इसलिए, माननीय सात न्यायाधीश और अन्य 20 न्यायाधीश, जैसा कि उल्लेख किया गया है, विरोधी पक्ष हैं /

उत्तरदाता और मैं एक शिकायतकर्ता। इस तरह से माननीय सात न्यायाधीशों ने एक स्वतः संज्ञान आदेश पारित किया जो अवैध और अनुचित है।

:

इसलिए मैं आपसे असंवैधानिक पीठ को रद्द करने का अनुरोध करता हूं और

मेरा सामान्य काम बहाल करें।

लेकिन, माननीय सात न्यायाधीशों ने मुझे अंदर जाने से रोक दिया है।

8.2.2017 से मेरा न्यायिक और प्रशासनिक कार्य पूरा करना

अब तक। इसलिए, मैं सभी सातों न्यायाधीशों को भुगतान करने के लिए बुला रहा हूं मुआवजे के रूप में ₹1 करोड़ (केवल चौदह करोड़ रुपये) की राशि, क्योंकि आपने मेरे और मेरे दिमाग को परेशान किया है।

सामान्य जीवन, इसके अलावा आपने भारत में 120 करोड़ की आबादी वाले आम जनता में मेरा अपमान किया है।

कानूनी ज्ञान। अब सभी सात न्यायाधीश इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों की अवधि के भीतर मुआवजे का एक हिस्सा का भुगतान करेंगे, जिसमें विफल रहने पर आपके समान रुख पर (समान)), मैं आपके न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों पर रोक लगाऊंगा।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

आपका,

एसडी /

(न्यायमूर्ति सी.
एस. कर्णन) "

ऊपर निकाले गए पत्र को भी आगे विस्तार की आवश्यकता नहीं है, और इस तरह, हम उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित नहीं करना चाहते हैं। न्यायमूर्ति कर्णन, आगे।

26. इस मामले में जारी जमानती वारंट, व्यक्तिगत प्राप्त करने के लिए

श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन की उपस्थिति उन्हें 17.3.2017 पर दी गई थी। विधिवत सेवा प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में उसी पर हस्ताक्षर करने के बाद, न्यायमूर्ति श्री सी. एस. कर्णन ने उस पर अपनी लिखावट में निम्नलिखित नोट दर्ज कियाः

" 23.1.2017 की मेरी शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है।

एक सुओ-मोटू अवमानना आदेश। उसी शिकायत पर, मैंने निर्देश दिया

सी. बी. आई. एक विस्तृत जांच करेगी और दिल्ली में संसद के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इन परिस्थितियों में जमानती वारंट को विधिवत खारिज कर दिया जाता है, आगे मैंने सीबीआई को आदेश दिया कि

उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों और महान्यायवादी के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज करें। के रूप में

ऐसे सभी सात न्यायाधीश उक्त अधिनियम के तहत अभियुक्त हैं। इसलिए

मैं माननीय सात न्यायाधीशों से न्याय और राष्ट्रीय कल्याण के हित में अपने-अपने पदों से इस्तीफा देने का आग्रह करता हूं। इसलिए यह

माननीय न्यायाधीशों को अवमानना ए को आगे बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है

आरई में, माननीय श्री न्याय ई। कर्णन {जगदीश सिंह खेहर, सीजेआईजे

मेरे खिलाफ आगे की कार्यवाही। अब से शिकायत

माननीय न्यायाधीशों और मेरे बीच एससी/एसटी अधिनियम के संबंध में,

मुझे आशा है कि भविष्य में माननीय न्यायाधीशों को ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ अवैध आदेश अन्यथा

अधिकारिता प्रणाली बिगड़ जाएगी, इसलिए मैंने जमानती को खारिज कर दिया

एल. डी. द्वारा प्रस्तुत आदेश। डी. जी. पी. और आई. जी "

श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन ने एक दिनांकित पत्र को भी संबोधित किया

इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ के सदस्यों को। उसी का पाठ, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" करने के लिएः

तारीखः

17.03.2017

1. न्याय "। जे. एस. के. "-भारत के मुख्य न्यायाधीश

2. न्याय "। डी. एम. "

:

3. जस्टिस ". जे. सी.

4. न्याय "। आर. जी. आर. जी. "

5. जस्टिस ". एम. बी. एल.

6 . न्याय ". पी. सी. जी.

7. न्याय "। के. जे. "

मेरे स्वामी, आज स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही में आपका जमानती आदेश दिनांक 10.3.2017, कलकत्ता उच्च न्यायालय सर्कल के शीर्ष पुलिस अधिकारी 31.3.2017 पर 10.30 के लिए निर्धारित जमानती वारंट को निष्पादित करने के लिए मेरे आवास पर आए। मैंने मना कर दिया।

वैध कारण बताने के बाद भी ऐसा ही होता है। आपके प्रभुओं की ओर से इस तरह के अपमानजनक कृत्य और अत्याचारों को आगे बढ़ाते हैं

एक दलित न्यायाधीश को पूरी तरह से शर्मिंदा करने के लिए अधिनियम पूरी तरह से कानून से बाहर है। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने आगे के उत्पीड़न को रोकें।

हमारे न्यायालयों की गरिमा और गरिमा को बनाए रखने का आदेश।

आपका,

* एसडी /

(न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन) "

27. 31.3.2017 (सुनवाई की अगली तारीख, 10.3.2017 के बाद) पर, श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, और अग्रिम प्रस्तुतियाँ दीं।

सुनवाई के दौरान, उन्होंने पीठ को निम्नलिखित हस्ताक्षरित पाठ, दिनांक 25.3.2017 भी सौंप दियाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[201
7] 9 एस सी आर।

" को।

तारीखः
25.03.2017

1. न्याय "। जे. एस. के. "-भारत के मुख्य न्यायाधीश

2. जस्टिस ". डी. एम.

23

3. जस्टिस ". जे. सी.

4. न्याय "। आर. जी.

34

5. न्याय "। एमबीएल.
6. न्याय "। पी. सी. जी

7. न्याय "। के. जे. "

1. अब मैं अपनी दिनांकित 23.1.2017 की शिकायत को बिना शर्त वापस लेता हूँ।

20 माननीय न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाते हुए कि वे बेईमानी कर रहे थे

उनका व्यवहार। माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित उक्त शिकायत भारत के मंत्री। इसलिए मैं इस माननीय न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि

मेरी शिकायत के बाद से स्वतः संज्ञान अवमानना की कार्यवाही बंद हो सकती है अब बल नहीं है।

न्यायालय की अवमानना की।
3. मैं भविष्य में आपके प्रभु की सलाह और दिशानिर्देशों का पालन करूंगा।

न्यायिक प्रणाली और उसकी अखंडता को बनाए रखने का आदेश।

4. मैं 11.6.2017 पर सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, इसलिए, मैं एक गहरा अनुरोध करता हूँ मुझे सभी के आशीर्वाद से पीठ से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देने के लिए

मेरे न्यायिक और प्रशासनिक कार्य को बहाल करने के लिए अपने प्रभुओं से प्रार्थना करें और इस प्रकार न्याय और बाध्यता प्रदान करते हैं।

आपका,

एसडी /

(न्यायमूर्ति सी.
एस. कर्णन) "

उपरोक्त संचार का अवलोकन, एक स्पष्ट त्रुटि को प्रकट करता है

न्यायमूर्ति कर्णन ने स्वीकार किया कि उन्होंने 20 न्यायाधीशों के खिलाफ नाम से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले दिनांकित पत्र को तथ्यात्मक रूप से संबोधित किया था। हालांकि, प्रस्तुतियों में

उन्होंने खुले न्यायालय में अपने पूर्व सहयोगी न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को दोहराया। चूंकि 31.3.2017 पर सुनवाई के दौरान श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन द्वारा की गई मौखिक दलीलें पूरी हो गई थीं।

ऊपर निकाले गए नोट की सामग्री के विपरीत, इस न्यायालय ने 31.3.2017 पर निम्नलिखित चौथा न्यायिक आदेश पारित किया:

आरई में, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

" 1. श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। उनसे बार-बार पूछा गया कि क्या वह सामग्री की पुष्टि करते हैं।

श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन ने आज अदालत में 25.03.2017 का पत्र व्यक्तिगत रूप से हमें सौंपा। उन्होंने किसी भी तरह से सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। इसलिए हम उनका लिखित जवाब मिलने के बाद ही मामले पर आगे बढ़ें। श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन से उनके द्वारा संबोधित विभिन्न पत्रों में इंगित तथ्यात्मक स्थिति का जवाब देने का आह्वान किया जाता है।

1

सुनवाई की अगली तारीख को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना। 2. श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन का बार-बार अनुरोध है कि वे

न्यायिक और प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी जानी चाहिए, अस्वीकार कर दी जाती है।

3. सुनवाई के लिए 01.05.2017,10.30 AM पर पोस्ट करें।

यह दर्ज करना उचित है कि उपरोक्त आदेश के आदेश दिए जाने के बाद, न्यायमूर्ति कर्णन ने चले जाते हुए टिप्पणी की कि वे जेल भेजा जाएगा, लेकिन वह इस अदालत के समक्ष फिर से पेश नहीं होगा।

28. अपने कथन के अनुसार, श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन सुनवाई की अगली तारीख (1.5.2017 पर) पर उपस्थित नहीं हुए। लेकिन सुनवाई के दौरान उनकी प्रस्तुतियों और उनके व्यवहार को देखते हुए

31.3.2017 , और लिखित पाठ (-दिनांकित 25.3.2017) के साथ इसकी तुलना करते हुए, इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह विचार था कि वह अपना बचाव करने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं हो सकता है। इसलिए, यह था कि उनकी चिकित्सा

जाँच का आदेश 1.5.2017 पर दिया गया था। उपरोक्त आदेश दिनांक 1.5.2017-कार्यवाही का पाँचवाँ न्यायिक आदेश, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 1. श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन को आई. डी. 1 पर नोटिस जारी करते हुए, इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि न्यायमूर्ति कर्णन किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक कार्य को संभालने से तुरंत परहेज करेंगे, जो हो सकता है

उनके द्वारा धारण किए गए पद को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सौंपा गया था। वह.

सभी न्यायिक सेवाओं को तुरंत वापस करने का भी निर्देश दिया गया था और

के महापंजीयक को उनके कब्जे में प्रशासनिक फाइलें

उच्च न्यायालय।

[2017] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. इन कार्यवाही की शुरुआत के बाद से ही वह इस अदालत के प्रति और अनादर व्यक्त कर रहे हैं, वे ऐसा भी कर रहे हैं

घोर दंड से मुक्ति के साथ प्रेस बयान। लेकिन आखिरी के बाद आदेश दिनांक 31.3.2017, के बारे में कहा जाता है कि उसने आदेश जारी किए थे (कथित रूप से

न्यायिक होना) इस पीठ के सदस्यों के खिलाफ, और साथ ही, इस न्यायालय के एक अन्य माननीय न्यायाधीश के खिलाफ। उन आदेशों को प्राप्त किया गया है

इस न्यायालय की रजिस्ट्री, और वर्तमान संकलन का हिस्सा हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई न्यायालय नहीं। न्यायाधिकरण, आयोग या प्राधिकरण श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन द्वारा पारित आदेशों का संज्ञान लेते हुए, हम एतद्द्वारा सभी न्यायालयों, न्यायाधिकरणों को रोकते हैं। आयोग या

अधिकारीगण, हमारे द्वारा 8.2.2017 पर कार्यवाही शुरू करने के बाद, श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन द्वारा पारित किसी भी आदेश का संज्ञान लेने से।

3. प्रेस ब्रीफिंग का सार, साथ ही, श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन द्वारा पारित कथित न्यायिक आदेश, प्रथम दृष्टया सुझाव देते हैं,

कि वह एक उपयुक्त चिकित्सा स्थिति में नहीं हो सकता है, अपना बचाव करने के लिए, वर्तमान कार्यवाही। इसलिए हम इसे उचित समझते हैं कि आगे बढ़ने से पहले उसकी चिकित्सकीय जांच की जाए। हम, तदनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशक को निर्देश देते हैं कि वे श्री न्यायमूर्ति सी. एस. की जांच करने के लिए पावलोव सरकारी अस्पताल, कोलकाता से डॉक्टरों का एक बोर्ड गठित करें।

कर्णन, और इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि क्या श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन अपना बचाव करने के लिए उपयुक्त स्थिति में हैं या नहीं। उपरोक्त बोर्ड 4.5.2017 पर परीक्षा आयोजित करेगा। द.

पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक एक दल का गठन करेंगे।

ऊपर अभिलिखित निर्देशों का पालन करने में चिकित्सा बोर्ड की सहायता करने के लिए पुलिस कर्मियों की संख्या।

4. चिकित्सा बोर्ड इस न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, या

8.5.2017 से पहले।

6. आगे के ऑर्डर के लिए 9.5.2017,10.30 AM पर पोस्ट करें। 7. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. एस. सूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, श्री अजीत कुमार सिन्हा ने एक मौखिक अनुरोध किया है, इन आरई, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन।

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

कि उन्हें इस न्यायालय में हस्तक्षेप करने और सहायता करने की अनुमति दी जा सकती है

मुद्दे के महत्व को देखते हुए। प्रार्थना की अनुमति है। द.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति है

- विवाद के गुण-दोष पर इस न्यायालय की सहायता करें।

उपरोक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि एक और दिशा थी

इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए विचित्र स्वतः संज्ञान न्यायिक आदेशों को ध्यान में रखते हुए

श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन द्वारा समय-समय पर पारित किया गया। तत्काल निर्देश द्वारा, न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, आयोगों और प्राधिकरणों को श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन द्वारा पारित किसी भी आदेश का संज्ञान नहीं लेने का निर्देश दिया गया था।

8.2.2017 , जिसमें उन्हें पहले से ही किसी भी चीज़ को संभालने से रोक दिया गया था

न्यायिक या प्रशासनिक कार्य।

29. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, हमारे लिए इस पर प्रकाश डालना आवश्यक नहीं है

श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन द्वारा मीडिया को दी गई सभी दलीलें,

साथ ही, उसके द्वारा पारित आदेश। ये सभी आदेश सार्वजनिक रूप से दिए गए थे।

डोमेन (न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा), इससे बहुत पहले इस न्यायालय को दिया गया था। मीडिया के साथ उनके साक्षात्कार और उनके द्वारा पारित आदेश

उन्होंने अनुसूचित के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

पीठ के सभी 7 सदस्य; 28.4.2017 दिनांकित एक अन्य आदेश द्वारा, वह वायु नियंत्रण प्राधिकरण, नई दिल्ली को 7 में से किसी को भी अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया।

बेनकली के सदस्य विदेश यात्रा करेंगे; और एक अन्य आदेश द्वारा दिनांकित 7 : 5.2017 , उन्होंने पीठ के सभी 7 सदस्यों और श्रीमती जस्टिस को सजा सुनाई।

66 " ...... आर. बी. आर. बी. "से 5 साल के कठोर कारावास तक। यह सब व्यापक था भारत में मीडिया के साथ-साथ विदेशी मीडिया द्वारा भी रिपोर्ट की गई। द.

बीबीसी ने भी इस मुद्दे पर रिपोर्ट की।

30. मामला अंततः 9.5.2017 पर सुनवाई के लिए लिया गया।

सुनवाई के दौरान विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने कहा,

पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए पीठ ने सूचित किया कि इस न्यायालय द्वारा 1.5.2017 पर जारी निर्देशों का अनुपालन,

निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, पश्चिम बंगाल सरकार का गठन किया गया था

पावलोव सरकारी अस्पताल, कलकत्ता से डॉक्टरों का एक बोर्ड

डॉक्टरों ने श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन से उनके आवास पर संपर्क किया था। पुलिस कर्मियों के साथ)। उन्होंने पीठ को यह भी सूचित किया कि न्यायमूर्ति कर्णन

डॉक्टरों के बोर्ड से मुलाकात की थी और उनसे बात की थी। न्यायमूर्ति कर्णन,

पीठ को सूचित किया गया, डॉक्टरों के बोर्ड को बताया गया कि वह स्वस्थ हैं

सी.

.

स्वास्थ्य की स्थिति, मानसिक और अन्यथा, और कोई चिकित्सा मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं थी। हमारा विचार है कि चिकित्सक मंडल के मनोचिकित्सक ऐसा करेंगे।

उपरोक्त बातचीत के दौरान न्यायमूर्ति कर्णन के मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के विरोध में रहे हैं। अगर उन्हें कुछ गलत मिलता, तो वे तदनुसार इस न्यायालय को सूचित किया है। चूंकि कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है

डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा, हम मान लेंगे, कि उन्हें रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त कुछ भी नहीं मिला था। इसलिए हम इस दावे को स्वीकार करेंगे।

न्यायमूर्ति कर्णन ने कहा कि वह अपना बचाव करने के लिए चिकित्सकीय और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं।

31. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, हमें विभिन्न संचारों के रूप में उनके द्वारा दिए गए बचाव पर भरोसा करना होगा।

समय-समय पर इस न्यायालय को भेजा जाता है, और सुनवाई के दौरान भी, जब वह 31.3.2017 पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं। कोई दूसरा नहीं है

हमारे साथ वैकल्पिक। हमने न्यायमूर्ति कर्णन को स्वतंत्रता प्रदान की थी। कारण दर्शाओ नोटिस पर अपना जवाब देने के लिए दिनांकित 1.5.2017 का आदेश (

8.5.2017) से पहले, स्पष्ट संकेत के साथ, कि यदि वह कोई प्रतिक्रिया दायर नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो न्यायालय यह मानते हुए मामले पर आगे बढ़ेगा कि उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है।

32. विवाद के गुण-दोष के आधार पर, इस न्यायालय को समय-समय पर विद्वान महान्यायवादी श्री मुकुल रोहतगी द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। वह.

सी. एस. कर्णन ने भी इस अदालत के सामने खुले तौर पर बड़ी संख्या में न्यायाधीशों की निंदा करते हुए अवमानना की थी। भ्रष्टाचार, और ऐसे आदेश पारित करके जिनमें न तो कोई कानूनी मंजूरी थी और न ही कोई औचित्य। श्री मनिंदर सिंह, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर

सुप्रीम कोर्ट बी. एसोसिएशन के अध्यक्ष और इसके उपाध्यक्ष श्री अजीत कुमार सिन्हा ने भी इस अदालत की सहायता की। वे अपनी दलील में भी स्पष्ट थे कि श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन लगातार और बार-बार आपराधिक अवमानना करने के दोषी थे। श्री के. के. वेणुगोपाल, कुलसचिव का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील मद्रास उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता ने अन्य सभी विद्वान वकीलों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि इस मामले में अंतिम निर्णय तब तक के लिए स्थगित किया जाए जब तक कि श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन अपने आई. एन. आर. ई., माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन को सेवानिवृत्त नहीं कर देते।

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद। यह प्रस्तुत किया गया था कि श्री न्यायमूर्ति

सी. एस. कर्णन, 11.6.2017 पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे। यह आग्रह किया गया कि यदि न्यायमूर्ति श्री सी. एस. कर्णन को अवमानना के लिए दंडित किया जाता है तो संस्थान की छवि को धूमिल किया जाएगा।

न्यायालय का, जबकि वह उच्च संवैधानिक पद धारण कर रहा है।

33. हमने तथ्यात्मक पर विचारपूर्वक विचार किया है।

यहाँ ऊपर देखी गई स्थिति, साथ ही, विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ, जिन्होंने सुनवाई के दौरान हमारी सहायता की। हम सावधानी से

श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन द्वारा समय-समय पर लिखे गए पत्रों के पाठ की जांच की गई। हमने स्वतः संज्ञान प्रक्रिया की बारीकी से जांच की है।

उनके द्वारा अपनाया गया, जिसके द्वारा उन्होंने अवमानना के लिए नोटिस जारी करने से पहले ऐसे आदेश पारित किए जो न्याय प्रशासन के लिए अपमानजनक थे, इस न्यायालय द्वारा। हमने पारित आदेशों का भी सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है।

श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन सुओ-मोटो (के कथित अभ्यास में

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उनके अधिकार क्षेत्र में,

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के साथ पढ़ें), इसके बाद भी

इस न्यायालय द्वारा उसे अवमानना नोटिस जारी करना। इस अदालत के पारित होने के बाद उनका व्यवहार और अधिक आक्रामक हो गया था।

समय-समय पर आदेश, इस मामले में। उनके द्वारा संबोधित पत्रों की सामग्री में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ निंदनीय सामग्री थी

और सर्वोच्च न्यायालय। इस पत्राचार को शासन के तीनों अंगों-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारियों को संबोधित किया गया था। उनके सार्वजनिक बयानों ने न्यायिक प्रणाली को हंसी के पात्र में बदल दिया। स्थानीय मीडिया, बेपरवाह

इससे न्यायिक संस्थान को जो नुकसान हो रहा था, वह खुशी-खुशी कर्णन लहर पर सवार हो गया। यहां तक कि विदेशी मीडिया ने भी भारतीय न्यायपालिका पर निशाना साधा था। उनके किसी भी कार्य को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है, विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा 8.2.2017 पर जारी किए गए स्पष्ट निर्देशों को देखते हुए, जिसमें उन्हें किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक कार्य के निर्वहन से बचने की आवश्यकता होती है। उनके स्वतः संज्ञान अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए, इस न्यायालय द्वारा 1.5.2017 पर एक और आदेश पारित किया जाना था, जिसमें न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, आयोगों और अधिकारियों को न्यायमूर्ति द्वारा पारित किसी भी आदेश का संज्ञान लेने से रोका गया था।

कर्णन।

17

34. हमारा विचार है कि न्यायमूर्ति कर्णन ने बचाव किया

स्वयं अपने कार्यों से, अपनी स्थिति को एक कम विशेषाधिकार प्राप्त जाति से संबंधित बताते हुए। उपरोक्त पद ग्रहण करके, उन्होंने अप्रिय स्थिति पैदा कर दी

सर्वोच्च न्यायालय के असंख्य न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप, मुख्य न्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 9 एस
सी आर।

टी

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, लेकिन ज्यादातर मद्रास के न्यायाधीशों के खिलाफ
अदालत। न्यायाधीशों की सूची जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे
स्टाइस कर्णन में निम्नलिखित शामिल हैं:

न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर-भारत के मुख्य न्यायाधीश,

1 .

न्यायमूर्ति पी. सतशिवम-भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश,

2 .

न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर-भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश,

3 .

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा-न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय,

4 .

न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर-न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय,

5 .

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई-न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय,

6 .

न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर-न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय,

7 .

न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष-न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय

8 .

भारत का,

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ-न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय,

9 .

न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल-न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय,

10 .

न्यायमूर्ति आर. भानुमति-न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय,

11 .

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल-न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय

12 .

भारत,

न्यायमूर्ति एफ. एम. आई. कलीफुल्ला-पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय

13 .

भारत का,

न्यायमूर्ति एम. वाई. इकबाल-पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय

14 .

भारत,

न्यायमूर्ति एस. के. अग्निहोत्री-मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय

15 .

सिक्किम,

न्यायमूर्ति आर. सुधाकर-न्यायाधीश, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय

16 .

कश्मीर,

न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन-न्यायाधीश, उच्च न्यायालय

17 .

हैदराबाद में न्यायपालिका

न्यायमूर्ति एस. मणिकुमार-न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय,

18 .

न्यायमूर्ति एस. नागमुथु-न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय,

19 .

20 .

न्यायमूर्ति एम. सत्यनारायणन-न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय, आईएनआरई, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन [जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई]

21 .

न्यायमूर्ति सी. टी. सेल्वम-न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय,

न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन-न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय,

22 .

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश-न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय,

23 . 24 .

न्यायमूर्ति टी. राजा-न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय,

न्यायमूर्ति के. स्वामीदुरई-पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय

25 .

4

मद्रास,

न्यायमूर्ति चित्रा वेंकटरमन-पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय

26 .

मद्रास के,

27 .

न्यायमूर्ति के. एन. बाशा-पूर्व न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति वी. धनपालन-पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय

28 .

मद्रास,

:

न्यायमूर्ति एस. तमिलवनन-पूर्व न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय,

29 .

30 .

न्यायमूर्ति एलिपे धर्म राव-पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय

मद्रास,

31. न्यायमूर्ति आर. एस. रामनाथन-पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय

मद्रास,

32 .

न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन-पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय

मद्रास,

न्यायमूर्ति जी. एम. अकबर अली-पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय

33 .

मद्रास।

35. न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा लगाए गए आरोपों में से कोई भी नहीं था।

किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित। उनके आरोप दुर्भावनापूर्ण थे और

मानहानिकारक, और स्पष्ट रूप से नाम से, कई संबंधित लोगों के खिलाफ

न्यायाधीश। उन्होंने अपने आक्षेपों को पहले बड़े पैमाने पर जनता के सामने रखा।

उदाहरण के लिए, उनके पत्रों का सावधानीपूर्वक समर्थन करके ताकि व्यापक रूप से प्रसारित किया जा सके

उनके संचार की सामग्री, वांछित वृत्तों के लिए। उनमें से कुछ पत्रों का जानबूझकर समर्थन किया गया था, दूसरों के बीच, राष्ट्रपति को

तमिलनाडु अधिवक्ता संघ। और बाद में, इंटरनेट के माध्यम से,

उन्होंने अपने दृष्टिकोण और पूरी सामग्री को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा।

तत्काल अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान, उनका उपहास

:

उच्चतम न्यायालय बेरोकटोक बना रहा। वास्तव में, यह ऊँचा था, के रूप में पहले कभी नहीं। इस प्रक्रिया में उन्होंने इसके द्वारा पारित आदेशों पर भी रोक लगा दी।

अदालत। उनके द्वारा पारित आदेशों में से एक ने इस सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर न्यायाधीशों को प्रतिबंधित कर दिया

[20
17] 9 एस सी आर।

बेंच, देश छोड़ने से। एक अन्य आदेश द्वारा उन्होंने दोषी ठहराया

इस पीठ के न्यायाधीशों ने, इस न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश के अलावा, और सजा सुनाई

उन पर व्यक्तिगत लागत लगाने के अलावा 5 साल के कारावास की सजा

दोषी ठहराए गए न्यायाधीश। संक्षेपित तथ्यात्मक स्थिति की पृष्ठभूमि में ऊपर, 9.5.2017 पर स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए,

हमने निर्देश दिया था कि श्री न्यायमूर्ति सी. एस. द्वारा आगे कोई बयान जारी नहीं किया जाए। कर्णन का प्रचार किया जाएगा। हालाँकि, तत्काल प्रतिबंध आदेश इस मामले पर किसी भी सार्वजनिक बहस को रोकता या बाधित नहीं करता है, शैक्षणिक या

अन्यथा। हमने मीडिया को ऊपर व्यक्त की गई सीमित सीमा के अलावा किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया है। हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि

सार्थक बहस से सभी संभावित दृष्टिकोणों से इस मुद्दे की पूरी समझ बनेगी।

36. पूर्ववर्ती परिच्छेदों में व्यक्त कथन से,

हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कामनान की कार्रवाई अदालत की अवमानना की सबसे बड़ी और गंभीर कार्रवाई थी।

उन्होंने अदालत के सामने अवमानना भी की है। इसलिए, वह अपने अप्रिय कार्यों और व्यवहार के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी है। हम संतुष्ट हैं कि उन्हें उनके उपरोक्त कार्यों के लिए छह महीने के कारावास के साथ दंडित किया जाना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया।

ध्यान दें: तत्काल में सभी उद्धरणों में दिया गया जोर

फैसला, हमारे हैं।

चेलामेश्वर, जे. 1. यह मामला कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है।

सवाल करते हैं। मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के फैसले में विस्तार से दी गई है। इसलिए, हम प्रस्ताव करते हैं

केवल न्यूनतम का उल्लेख करना।

2. द्वारा पदोन्नति के लिए अवमानक के नाम की सिफारिश की गई थी

मद्रास उच्च न्यायालय का कॉलेजियम अर्थात तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और दो

वरिष्ठतम न्यायाधीश। संविधान के तहत विचार की गई आवश्यक नियुक्ति प्रक्रिया के अनुष्ठान के पूरा होने के बाद, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों में व्याख्या की गई थी, उन्हें नियुक्त किया गया था।

30 मार्च 2009 को।

3. क्या अवमानकर्ता का आचरण उसके बाद का है

पदोन्नति न्यायपालिका के एक सदस्य से अपेक्षित शिष्टाचार के पारंपरिक रूप से स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप है-विशेष रूप से एक संवैधानिक अदालत को एक पहेली बने रहना चाहिए। अवमानकर्ता की आदत रही है कि

' सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. भारत संघ (1993) 4 एस. सी. सी. 441 और 1998 (1998) का विशेष संदर्भ संख्या 1 7 एस. सी. सी. 739 आर. ई., माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

[चेलामेश्वर, जे।]

न्यायाधीशों और बाद के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा भ्रष्टाचार और विभिन्न अपराधों के आरोपों वाले पत्रों को संबोधित करना मद्रास उच्च न्यायालय। उनमें से कुछ पत्रों की सामग्री का उल्लेख माननीय मुख्य न्यायाधीश के फैसले में किया गया है। उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान कार्यवाही किसी भी मामले में जांच नहीं है।

अवमानकर्ता द्वारा लगाए गए उन आरोपों में से एक या क्या अवमानकर्ता की गतिविधि एक के लिए अनुमेय आचरण की सीमाओं के भीतर है

इस देश में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। हमारी राय में, इस न्यायालय के दिनांक 9 मई, 2017 के आदेश द्वारा दोषसिद्धि और सजा दर्ज करने के लिए प्रासंगिक तथ्य सीमित हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित पदाधिकारी। इन पत्रों में आरोप (1) थे कि संविधान के न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया इस देश की अदालतें अस्वास्थ्यकर हैं, (2) विभिन्न के खिलाफ भ्रष्टाचार

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, आयोग के (3)

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक के खिलाफ कुछ अपराधों (बलात्कार) और (4) मद्रास उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों का आचरण

न्यायालय जो (अवमानक के अनुसार) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराधों का गठन करता है, 1989. इन विभिन्न आरोपों का विवरण प्रधानमंत्री को संबोधित उपर्युक्त पत्रों और अन्य दस्तावेजों में पाया जाता है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के फैसले में संदर्भित इस न्यायालय के प्रशासनिक रिकॉर्ड का एक हिस्सा हैं।

5. क्या अवमानकर्ता द्वारा लगाए गए वे विभिन्न आरोप हैं

आरोपों की सच्चाई को स्थापित करने के लिए किसी भी साक्ष्य के आधार पर एक ऐसा मामला है जिसकी इन कार्यवाही में जांच नहीं की जा सकती है। ये हैं आरोप

बहुत अस्पष्ट और उनमें से कुछ असंगत भी हैं। चाहे कोई भी अवमानकर्ता द्वारा निर्दिष्ट मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उन कथित कुकर्मों को देश के किसी भी कानून के तहत कोई अपराध या कार्रवाई योग्य गलत माना जाता है, जिसकी जांच की आवश्यकता होती है। यदि अवमानकर्ता विश्वास करता है और उसके पास यह स्थापित करने के लिए सामग्री है कि कुछ न्यायाधीश

मद्रास उच्च न्यायालय कानून द्वारा ज्ञात कुछ अपराधों के लिए भ्रष्ट या अन्यथा दोषी है, उसे उपयुक्त मंच से संपर्क करने की आवश्यकता है

उन आरोपों की जांच करने के लिए। उचित मंच और प्रक्रिया क्या है जिसका अवमानकर्ता को कानून बनाने के लिए पालन करना आवश्यक है?

* पत्र संख्या 1-दिनांकित 03.01.2017 और पत्र No.II-दिनांकित नहीं, लेकिन कभी-कभी फरवरी 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अवमानकर्ता द्वारा लगाए गए प्रत्येक आरोप आर. टी.

जिन प्रश्नों की विस्तार से जांच की जानी चाहिए।

6. ऐसी शिकायतें, यदि उपयुक्त मंच/प्राधिकरण को की जाती हैं

प्रक्रिया के अनुसार जाँच की आवश्यकता है

उन आरोपों में से प्रत्येक के संदर्भ में प्रासंगिक कानून द्वारा स्थापित और उचित आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू की जानी है, यदि जांच से किसी भी संज्ञेय या गैर-संज्ञेय अपराध के होने का पता चलता है।

संज्ञेय या कोई अन्य कार्रवाई योग्य गलत।

7. यदि अवमानकर्ता द्वारा उनके द्वारा नामित किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोपों में से किसी एक में कोई सच्चाई है, तो यह बहुत गंभीर है।

शिकायतकर्ता या सूचना देने वाला। यदि अवमानकर्ता द्वारा लगाए गए किसी एक या सभी आरोपों की उचित जांच शुरू की जाती है, तो वह इस पर विचार करेगा। उसके द्वारा लगाए गए आरोपों की सच्चाई को स्थापित करने के लिए एक गवाह के रूप में।

दुर्भाग्य से अवमानकर्ता एक से अनजान प्रतीत होता है

कानून के मूल सिद्धांत कि एक शिकायतकर्ता/सूचना देने वाला अपनी शिकायत में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। अवमानकर्ता ने एक से अधिक अवसरों पर "अपने न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने के लिए आदेश पारित किए"

आरोपों के आधार पर मद्रास उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए राज्यों के विभिन्न प्राधिकरणों को आदेश देना।

समय-समय पर उसके द्वारा किया जाता है।

9. क्या उपरोक्त सभी आचरण दोनों में से किसी एक के बराबर हैं

" भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 (1) (बी) के साथ पठित अनुच्छेद 124 (4) के अर्थ के भीतर दुर्व्यवहार "या" असमर्थता "साबित हुई

जाँच। यदि अवमानकर्ता मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोपों को साबित करने में असमर्थ है, तो इस तरह की विफलता से क्या कानूनी परिणाम होंगे, इसकी भी जांच की आवश्यकता है। शायद, अवमानकर्ता किसी भी अन्य कानूनी के अलावा दीवानी और आपराधिक मानहानि के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

परिणाम। 10. लेकिन जिस बारंबारता और गंभीरता के साथ अवमानकर्ता ने अपने सहयोगियों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए और जिस तरह से इस तरह के आरई, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

.

[चेलामेश्वर,

जे.]

आरोप सार्वजनिक किए जाते हैं, निश्चित रूप से उन व्यक्तिगत न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनके खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय की छवि और शायद इस देश में न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कम करने की संभावना है। नतीजतन,

अवमानक की गतिविधि को यह निर्धारित करने के लिए जांच की आवश्यकता है कि क्या

अवमानकर्ता के आरोपों पर कार्रवाई करना। लेकिन यह अपमान करने वाले को नहीं रोक पाया। उनकी गतिविधि बेरोकटोक जारी रही। 11. इसलिए, इस बात की जांच करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई कि क्या अवमानकर्ता का आचरण अदालत की अवमानना है। अगर केवल

अवमानकर्ता ने न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में उचित रूप से भाग लिया, एक सही उत्तर पाया जा सकता था।

12. लेकिन एक बात निश्चित प्रतीत होती है। अगर ऊपर बताया गया है

आचरण अवमानना है, यह निश्चित रूप से केवल आपराधिक अवमानना हो सकती है

न्यायालय को बदनाम करने के शीर्ष के अंतर्गत आता है।

13. अवमानकर्ता के लगातार संदिग्ध आचरण के परिणामस्वरूप एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना करने से शायद भारत के मुख्य न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उपरोक्त सभी-उल्लिखित

न्यायिक पक्ष से इस न्यायालय द्वारा प्रश्नों की बेहतर जांच की जा सकती है। हम इस न्यायालय के अधिकार/क्षेत्राधिकार पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं

अवमानना कार्यवाही। काल्पनिक रूप से कहें तो अगर कोई यह आरोप लगाते हुए इस अदालत का रुख करता है कि न्यायमूर्ति कर्णन की गतिविधि अदालत की अवमानना के समान है और इसलिए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए

यह न्यायालय प्रश्नों की जांच करने के लिए बाध्य है। हो सकता है कि उसने स्वीकार किया हो या प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन इस तरह की याचिका की जांच करने के लिए इस न्यायालय का अधिकार या अधिकार क्षेत्र, यदि किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। इसलिए, हमारी राय में, यह तथ्य कि वर्तमान अवमानना कार्यवाही शुरू की गई है

इस न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेने से इसकी रखरखाव क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि केवल अवमानकर्ता ने कार्यवाही में उचित रूप से भाग लिया होता, तो उपरोक्त सभी प्रश्नों और शायद उनके लिए कई और प्रासंगिक प्रश्नों की ठीक से जांच की जा सकती थी और आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते थे।

दर्ज किए गए हैं। 14. दुर्भाग्य से, अवमानकर्ता ने कभी भी जांच को सही दिशा में नहीं जाने दिया। दूसरी ओर, उन्होंने अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाने का फैसला किया

इस न्यायालय का उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए, न कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर

[201
7] 9 एस सी आर।

इस आधार पर कि उसकी गतिविधि अवमानना नहीं थी, बल्कि जमीन पर थी

कि एक न्यायाधीश के खिलाफ कोई अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है

उच्च न्यायालय। अवमानकर्ता के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ एकमात्र संभावित कानूनी कार्रवाई उसे उसके अनुसार पद से हटाना है।

संविधान के तहत निर्धारित महाभियोग की प्रक्रिया के साथ - उसका "आचरण" और "दुराचार" जो भी हो, एक ऐसा रुख जो स्पष्ट रूप से कानून में असमर्थनीय है। वह वहाँ नहीं रुका। उनका मानना था कि इस न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से एक

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत अपराध (रोकथाम)

अत्याचार) अधिनियम, 1989 के रूप में अवमानक उन समुदायों में से एक से संबंधित है जो उस अधिनियम के सुरक्षात्मक दायरे में आता है। वह न केवल ऐसा मानते थे, बल्कि निश्चित रूप से ऐसा करने का इरादा भी रखते थे

इस पीठ के सदस्यों के खिलाफ, जिसका विवरण दिया गया है पैराग्राफ 22 से 26। वास्तव में, (i) उन्होंने सदस्यों पर इस बात का आरोप लगाया

उनके खिलाफ पूर्वाग्रह का दोषी पीठ, (ii) "उन्होंने घोषणा की" कि दीक्षा

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत अपराध का गठन करने से जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।

15. इससे पहले कि हम उन कारणों को दर्ज करें जिन्होंने हमें एक होने के लिए प्रेरित किया

9 मई, 2017 के आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले, हम अनुचित कार्रवाई के अपराधियों को दंडित करने के लिए संवैधानिक अदालतों के अधिकार की प्रकृति को संक्षेप में इंगित करना उचित समझते हैं। 16. अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने के अधिकार का प्रयोग न्यायपालिका द्वारा हमेशा से किया जाता रहा है। के लिए औचित्य

3 इस विषय से संबंधित सबसे शुरुआती कानूनी घोषणाओं में से एक में, न्यायमूर्ति विल्मोट ने रेक्स बनाम. एल्मन (1765) विल्मोट के नोट्स, 243 ने अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति के पीछे के दर्शन को समझाया। मार्ग अब एक क्लासिक प्रदर्शनी इस प्रकार हैः

" और जब भी कानून के प्रति पुरुषों की निष्ठा को मौलिक रूप से हिलाया जाता है, तो यह न्याय की सबसे घातक और सबसे खतरनाक बाधा है और मेरी राय में किसी भी बाधा की तुलना में अधिक तेजी से और तत्काल निवारण का आह्वान करता है, न कि न्यायाधीशों के लिए निजी व्यक्तियों के रूप में, बल्कि इसलिए कि वे न्याय के माध्यम हैं।

जिसे राजा का न्याय लोगों तक पहुँचाया जाता है।

आरई में, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

[चेलामेश्वर, जे।]

इसका अस्तित्व व्यक्तिगत न्यायाधीशों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की पवित्रता और प्रभावशीलता में विश्वास पैदा करने के लिए है, हालांकि वे अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति से नहीं आते हैं और न ही आने चाहिए।

उन्हें अधिक निश्चित नींव पर आराम करना चाहिए। नींव लोगों का विश्वास और विश्वास है कि न्यायपालिका निडर है और

निष्पक्ष।

17. अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति को हमेशा कुछ उच्च न्यायालयों में अंतर्निहित माना गया है और अन्य में इसे कानूनों द्वारा प्रदान किया गया था।

18. ई. एम. शंकरन नम्बूदरीपद बनाम में यह न्यायालय। टी.

नारायणन नाम्बियार, (1970) 2 एस. सी. सी. 325 ने कहाः

" 6. अवमानना का कानून अदालतों के कारावास से दंडित करने या शब्दों या कार्यों के दोषी व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने के अधिकार से उत्पन्न होता है।

जो या तो न्याय के प्रशासन में बाधा डालते हैं या बाधा डालते हैं। इस अधिकार का प्रयोग भारत में सभी न्यायालयों द्वारा अवमानना के समय किया जाता है।

इन फेसी क्यूरी और उनके डी पर वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रतिबद्ध है

अपनी ओर से या उनके अधीनस्थ न्यायालयों की ओर से, भले ही अदालतों के बाहर किया गया। पूर्व में, इसे अंतर्निहित माना जाता था

अभिलेख न्यायालय की शक्तियों में और अब संविधान द्वारा

भारत का, यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का एक हिस्सा है और

उच्च न्यायालय। ......

19. इस न्यायालय ने एक से अधिक अवसरों पर अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति की प्रकृति और दायरे की जांच की। आर. एल. कपूर बनाम मद्रास राज्य, (1972) 1 एस. सी. सी. 651, इस न्यायालय ने इस प्रश्न की जांच की कि क्या

मद्रास उच्च न्यायालय की स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1952 के तहत उत्पन्न हुई। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" पैरा 5. ...... अनुच्छेद 215 घोषणा करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय

अभिलेख न्यायालय और उसके पास स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। क्या अनुच्छेद 215

4 " अवमानना का कानून उन न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए नहीं बनाया गया है जो जनमत की हवाओं के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। न्यायाधीशों को धैर्यवान व्यक्ति माना जाता है, जो कठोर जलवायु में पनपने में सक्षम होते हैं। [डगलस, जे., क्रेग बनाम। हार्नी, 331 यू. एस. 367,376 (1947)] 5 "न्यायालय की अवमानना के मामले में न्यायालय द्वारा लागू अनुशासन का उद्देश्य न्यायालय या न्यायाधीश के व्यक्ति की गरिमा को सही साबित करना नहीं है, बल्कि न्याय के प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप को रोकना है।" [बोवेन, एल. जे.-हेलमोर बनाम। स्मिथ, (1887) 35 Ch D 449,455] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2017] 9 एस सी आर।

उच्च न्यायालय की शक्ति घोषित करता है जो पहले से ही इसमें मौजूद है इसके रिकॉर्ड की अदालत होने का कारण, या क्या लेख प्रदान करता है

अभिलेख न्यायालय में निहित शक्ति, अधिकारिता एक विशेष है, जो न्यायालयों की अवमानना से उत्पन्न या व्युत्पन्न नहीं होती है।

अधिनियम, 1952। किसी भी मामले में, जहां तक स्वयं उच्च न्यायालय की अवमानना का संबंध है, जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय से अलग है।

संविधान इन अधिकारों को प्रत्येक उच्च न्यायालय में निहित करता है, और

इसलिए विधानमंडल का कोई भी अधिनियम उस अधिकार क्षेत्र को छीन नहीं सकता और

इसे अपने अधिकार के आधार पर नए सिरे से प्रदान करें। ...... "

इसके बाद, प्रीतम पाल बनाम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 1993, सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 529, इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने राय दी कमियाँः

पैरा 15. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 से पहले, यह अभिनिर्धारित किया गया था

कि उच्च न्यायालय के पास अपनी अवमानना से संक्षिप्त रूप से निपटने और अपनी प्रक्रिया अपनाने की अंतर्निहित शक्ति है, बशर्ते कि यह अवमानकर्ता को बचाव करने का एक उचित और उचित अवसर प्रदान करे।

स्वयं। लेकिन प्रक्रिया अब प्रविष्टि 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 15 द्वारा निर्धारित की गई है,

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III। यद्यपि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का अवमानना क्षेत्राधिकार

संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत 'अभिलेख न्यायालय' घोषित करके और इसलिए, अंतर्निहित शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को हटाया नहीं जा सकता है

संवैधानिक संशोधन से कम किसी भी कानून द्वारा।

इसने आपराधिक अवमानना को बढ़ावा देने वाली आपत्तिजनक कार्रवाई के विभिन्न रूपों का संकेत दिया। अदालत को बदनाम करना उनमें से एक है।

" अवमानना के कई प्रकार हैं। अवमानना के मुख्य रूप न्यायाधीशों का अपमान, उन पर हमले, निष्पक्ष सुनवाई के प्रति पूर्वाग्रह की प्रवृत्ति के साथ लंबित कार्यवाही पर टिप्पणी, अदालतों के अधिकारियों, गवाहों या पक्षों के लिए बाधा, अवमानना की प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं।

न्यायालय, न्यायालय से जुड़े अधिकारियों द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन और न्यायाधीशों या न्यायालयों को बदनाम करना। अंतिम रूप आता है,

आम तौर पर बोलते हुए, जब किसी व्यक्ति का आचरण 1 लाता है

आरई में, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

टी.

[चेलामेश्वर, जे।]

अनादर में कानून का अधिकार और प्रशासन या

उपेक्षा करें। इस आचरण में वे सभी कार्य शामिल हैं जो

अदालत की बदनामी या अनादर या जो इसकी गरिमा को आहत करता है, इसकी महिमा का अपमान करता है या इसके अधिकार को चुनौती देता है। ऐसी अवमानना हो सकती है एकल न्यायाधीश या एकल न्यायालय के संबंध में प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, पूरे न्यायालय के संबंध में प्रतिबद्ध हो सकता है।

न्यायपालिका या न्यायिक प्रणाली "।

20. इस तरह की शक्ति का प्रयोग हमेशा बहुत कम हुआ है।

और कुछ अनुशासन के अधीन। न्यायपालिका के सदस्य हमेशा इस तथ्य के प्रति सचेत रहे हैं कि अवमानना की शक्ति का प्रयोग सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल पूरी तरह से किया जाना चाहिए।

ईमानदारी के सक्रिय प्रकाश के संपर्क में आना, भले ही थोड़ा अधिक-उत्साही हो, आलोचना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्याय कोई गुप्त गुण नहीं है। ”

6 * ई. एम. शंकरन नम्बूदरीपाद बनाम टी. नारायणन नांबियार, (1970) 2 एससीसी 325, पैरा 6

7 1 श्री बरदकांत मिश्रा बनाम। उड़ीसा उच्च न्यायालय के पंजीयक और एक अन्य, (1974) 1 एस. सी. सी. 374 (माननीय। अय्यर, जे.-अलग लेकिन सहमत राय)

" पैरा 65। इस मामले में उठाए गए न्यायालय की अवमानना के पहलुओं से संबंधित कानून के सिद्धांतों को बताने से पहले हम लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए पर्याप्त रेखाएं स्पष्ट करने की आवश्यकता को रेखांकित करना चाहेंगे कि इस प्राचीन और अंतर्निहित शक्ति का उपयोग जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए नहीं किया जाएगा। एक अस्पष्ट और भटकना

अनिश्चित सीमाओं के साथ अधिकार क्षेत्र, अभियोजक को दंडित करने की एक संवेदनशील और संदिग्ध शक्ति, एक ऐसा कानून जो सच्चाई और सार्वजनिक भलाई की परवाह किए बिना प्रकाशित करना अपराध बनाता है और संक्षिप्त मनु दोषसिद्धि की प्रक्रिया की अनुमति देता है, अनजाने में नागरिक स्वतंत्रताओं पर खाई डाल सकता है और इसलिए अवमानना शक्ति से संबंधित विशेष अधिकार क्षेत्र और न्यायशास्त्र को विचार-विमर्श के साथ चित्रित किया जाना चाहिए और गंभीर रूप से संचालित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायिक क्षेत्रों द्वारा निरीक्षण। इसलिए यह है कि हमारी स्वतंत्रता के पैलेडियम के रूप में, सर्वोच्च

न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक अपमान के खिलाफ भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सतर्कता से रक्षा करनी चाहिए-एक नाजुक लेकिन पवित्र कर्तव्य जिसका निर्वहन किया जाता है

एक उच्च क्रम की सहिष्णुता और अलगाव की मांग करता है।

पैरा 67. जिस तरह के विचार हमने किए हैं, उससे अदालतों की अवमानना अधिनियम, 1971 को लागू किया गया, जो पारंपरिक कानून से कुछ प्रतिबंधात्मक विचलन करता है और कुछ अच्छे सिद्धांतों को इंगित करता है जो अनकहे के रूप में काम करते हैं।

कानून की इस शाखा में दिशानिर्देश। ...... "

8 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ 409 [2017] 9 एस. सी. आर. पर पैरा 82।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लगभग एक दशक पहले दिए गए एक फैसले में, हम में से एक (गोगोई,

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 14. न्यायपालिका आलोचना के प्रति अतिसंवेदनशील नहीं है; वास्तव में, प्रामाणिक है। आलोचना का स्वागत है, शायद इसलिए कि यह आत्म-आत्मनिरीक्षण के द्वार खोलती है। न्यायाधीश त्रुटिहीन नहीं होते हैं; वे मनुष्य हैं और वे

हालाँकि, अक्सर अनजाने में और अपनी व्यक्तिगत धारणाओं के कारण गलती करते हैं। ऐसी स्थिति में, न्यायिक घोषणा में या यहां तक कि अन्य रूपों में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की उचित आलोचना

न्यायिक आचरण, जनहित और सार्वजनिक भलाई के अनुरूप है जिसे न्यायाधीश सेवा देने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। की प्रणाली

इसलिए न्याय प्रशासन को उचित प्रोत्साहन मिलेगा।

न्यायाधीशों के बीच इस अहसास से कि वे अपने निर्णयों में गलती कर सकते हैं या वास्तव में कर चुके हैं; एक अन्य दृष्टिकोण, एक नया आयाम या अंतर्दृष्टि, इसलिए, हमेशा स्वागत योग्य होनी चाहिए। इस तरह की अनुभूति

जो वास्तव में कानून के शासन की महिमा को बढ़ाएगा, यह तभी संभव है जब न्यायाधीशों द्वारा दूसरों की राय के आलोक में आत्म-मूल्यांकन के दरवाजे खुले रखे जाएं।

16. लेकिन मौन कब एक विकल्प बने रहना बंद कर देना चाहिए? कहाँ है?

खींची जाने वाली रेखा? एक अवमाननापूर्ण कार्रवाई जनता के लिए गलत होने की कसौटी पर दंडनीय है जैसा कि अलग है

व्यक्तिगत न्यायाधीश को हुई हानि। न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास अपरिहार्य है। इसका क्षरण घातक है। बेशक, न्यायाधीश अपने स्वयं के आचरण, कार्रवाई और कर्तव्यों के प्रदर्शन से

जनता का विश्वास अर्जित करना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए, न कि अवमानना के नियम को लागू करके। आलोचना अंतर्निहित हो सकती है

न्यायिक निर्णय का सिद्धांत या इसका तर्क या तर्क और यहां तक कि इसकी शुद्धता भी। आलोचना एक व्यक्तिगत न्यायाधीश या न्यायाधीशों के समूह के आचरण की हो सकती है। आलोचना चाहे जो भी हो।

इसे भाषा और विषय वस्तु में गरिमापूर्ण बनाया जाना चाहिए क्योंकि अपरिष्कृत

अभिव्यक्तियाँ या अभिव्यक्तियाँ पहचान करने में अधिक सक्षम होती हैं। समग्र रूप से प्रणाली के साथ कथित गलत। उद्देश्य, व्यक्तिगत हित, पक्षपात, पूर्व-स्वभाव आदि को न्यायिक निर्णय के लिए जिम्मेदार होने के रूप में जिम्मेदार ठहराए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब तक कि, निश्चित रूप से, इसे एक मौजूदा तथ्य के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह वह है

अधिनियमों या प्रकाशनों की उपरोक्त श्रेणी जो इसके अंतर्गत आती है

अवमानना कानून में कार्रवाई की गारंटी देने वाली निषिद्ध डिग्री "।

(1) जी. एल. टी. 800: ललित कलीता और अन्य

आरई में, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

[चेलामेश्वर, जे।]

आर

इस देश में तब से वर्तमान कानूनी प्रणाली अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। दीवानी अवमानना को धारा 2 (बी) 1 के तहत "जानबूझकर" परिभाषित किया गया है। अदालत के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की अवज्ञा या अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन।

धारा 2 (सी) आपराधिक अवमानना को परिभाषित करती है। " धारा 2 (ग) "आपराधिक अवमानना" का अर्थ है प्रकाशन (चाहे

शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखे गए, या संकेतों द्वारा, या दृश्य द्वारा

किसी मामले का प्रतिनिधित्व, या अन्यथा) या कोई कार्य करना।

अन्य कार्य जो भी हो

(i) अपमान करता है या अपमान करने की प्रवृत्ति रखता है, या कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति रखता है

किसी न्यायालय का प्राधिकार; या

((ii) पूर्वाग्रह, या हस्तक्षेप करता है या देय में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है।

किसी न्यायिक कार्यवाही का पाठ्यक्रम; या

((ग) किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है या बाधा डालता है या बाधा डालता है।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि कोई भी कार्य जो न्यायालय के अधिकार को बदनाम करता है या बदनाम करता है और हस्तक्षेप करता है या

न्याय के प्रशासन में किसी भी तरह की बाधा दो प्रकार की होती है।

निंदनीय कार्रवाई।

22. यहाँ यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि ग्रेट ब्रिटेन जिसमें से हमने वर्तमान कानूनी प्रणाली 1 को अपनाया है, ने आपराधिक अपराध को समाप्त कर दिया है।

10 धारा 2 (बी) "दीवानी अवमानना" का अर्थ है किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना या किसी न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना।

11 " पैरा 34. यह देखा जाएगा कि परिभाषा में उपयोग की गई शब्दावली अंग्रेजी अवमानना के कानून से ली गई है और उन अवधारणाओं को मूर्त रूप देती है जो उस कानून से परिचित हैं, जिसे मोटे तौर पर भारत में लागू किया गया था। "निंदनीय", "न्यायालय के अधिकार को कम करना", "हस्तक्षेप", "बाधा" और "न्याय का प्रशासन" ये अभिव्यक्तियाँ हमारे उप-महाद्वीप की कानूनी मुद्रा में चली गई हैं और इन्हें उस अर्थ में समझना होगा जिसमें उन्हें अब तक हमारे न्यायालयों द्वारा अंग्रेजी कानून की सहायता से समझा गया है, जहां आवश्यक हो। - श्री बरदकांत मिश्रा का मामला फुटनोट 6 देखें

ऊपर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[201
7] 9 एस सी आर।

अदालत को बदनाम करने के आधार पर अवमानना

विधि आयोग की अनुशंसा दिनांक 12 दिसंबर, 2012 1

प्राप्त विभिन्न सुझावों पर चर्चा करने के बाद और उनके

निहितार्थ, विधि आयोग ने पैरा 91 में राय दीः

" 91. एक सवाल यह है कि क्या ये अपराध सक्षम हैं

के खिलाफ सामूहिक आरोप लगाने वाले प्रकाशनों को कवर करना

एक व्यक्तिगत न्यायाधीश के बजाय न्यायपालिका या इसका एक खंड। अगर

सामग्री पर्याप्त रूप से आक्रामक या खतरनाक है, यह सिद्धांत रूप में हो सकता है लोक व्यवस्था अधिनियम 1986 या संचार द्वारा कवर किया जाए

अधिनियम 2003। यह दुर्भावनापूर्ण संचार के दायरे में आने की संभावना नहीं है।

अधिनियम 1988 या उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 1997, जो ये मुख्य रूप से व्यक्तियों को लक्षित करने वाले आचरण से संबंधित हैं।

और अंत में पैरा 93 में अपने निष्कर्ष दर्ज किए। प्रासंगिक भाग

यह हैः

" 93 .

XXX

XXX

XXX

(11) कई वैधानिक अपराध हैं जिनमें अधिक शामिल हैं।

निंदात्मक व्यवहार के गंभीर रूप, और नागरिक

मानहानि की कार्यवाही झूठे मामले में उपलब्ध है।

भ्रष्टाचार या कदाचार के आरोप "।

और सिफारिश की गई " 94. तदनुसार, हम अपनी पहली पसंद को बदलने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

जैसा कि परामर्श पत्र में व्यक्त किया गया है, अर्थात्

प्रतिस्थापन के बिना अदालत को बदनाम करना। "

23. इस संबंध में अमेरिकी कानून अधिक उदार प्रतीत होता है।

बोलने की स्वतंत्रता पर अधिक जोर देना। हम नहीं चाहते कि

वर्तमान उद्देश्य के लिए अमेरिकी न्यायशास्त्र का कोई भी विस्तृत विश्लेषण करना। विधि आयोग से एक मार्ग उधार लेना

12 आपराधिक अवमानना के अपराध को समाप्त करने की सिफारिश करने के लिए विधि आयोग के विचार में से एक तथ्य यह है कि लोक व्यवस्था अधिनियम, 1986 और संचार अधिनियम, 2003 जैसे अन्य अधिनियम हैं जो उन स्थितियों पर पर्याप्त रूप से ध्यान दे सकते हैं जहां निराधार आरोप लगाए जाते हैं जो अन्यथा अदालत को बदनाम करने का अपराध होते।

" 80. एक ही व्यवहार के कई आपराधिक अपराध हैं।

जो अदालत को बदनाम कर सकता है, और ये जारी रहेंगे।

उपलब्ध होना चाहे अपमान का अपराध है या नहीं

निरस्त कर दिया गया "।

* आरई में, माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन

[चेलामेश्वर, जे।]

अदालत की अवमानना पर यूनाइटेड किंगडम की रिपोर्टः न्यायालय को बदनाम करना (न्यायालय की अवमाननाः अदालत "13 को बदनाम करना पर्याप्त होगाः

मानवाधिकारों के खिलाफ। 33 " अन्य सामान्य कानून देशों के संदर्भ में, कानून

आयोग ने स्थिति का सारांश इस प्रकार दियाः

" संयुक्त राज्य अमेरिका का कानून पारंपरिक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि अधिकार मानता है, जैसा कि प्रथम संशोधन में निहित है।

संघर्ष के मामले में अन्य सभी पर हावी है, जब तक कि कोई "स्पष्ट" न हो और वर्तमान खतरा है कि [शब्द] मूल लाएंगे

ऐसी बुराइयाँ जिन्हें कांग्रेस को रोकने का अधिकार है "[(1919) 249 यू. एस. 47,51

52 तक]। इंग्लैंड और वेल्स जैसे अन्य सामान्य कानून वाले देश

और ऑस्ट्रेलिया, इसके विपरीत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन इसे दूसरों के बीच एक अधिकार के रूप में मानता है। किसी भी संघर्ष को संतुलन अभ्यास के माध्यम से हल किया जा रहा है। [न्यायमूर्ति आर. सैकविल ने कहा, "अदालतें कितनी कमजोर हैं? बोलने की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की आलोचना "(2005)। हमारे परामर्श पत्र में

हमने उसी विरोधाभास की ओर ध्यान आकर्षित किया। कनाडा में स्थिति कोपीटो ((1987) 47 डी. एल. आर. (चौथा) में अदालत तक अनिश्चित रहा।

213 (ओ. एन. टी. सी. ए.)], निंदनीय अपराध को अस्वीकार करते हुए, संयुक्त राज्य के करीब एक दृष्टिकोण अपनाते हुए दिखाई दिया। नया।

न्यूजीलैंड ने कोपीटो [(1993) एन. जेड. एच. सी. 423 का अनुसरण करने से इनकार कर दियाः [1994)

एन. जेड. एल. आर. 48], इस प्रकार एंग्लो-ऑस्ट्रेलियाई शिविर में बने रहे।

24. हालाँकि, भारत में न्यायालय को बदनाम करना अभी भी न्यायालय की अवमानना करने वाले कार्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। 14 हालांकि गतिविधि क्या है

जो न्यायालय के अपमान का गठन करता है, परिभाषित नहीं है या बहुत अधिक है।

उपर्युक्त मामलों में सटीक रूप से समझाया गया है कि व्यक्तियों को इस आधार पर अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था कि उनके कार्यों ने उन्हें बदनाम किया था अदालत।

13 न्यायालय की अवमानना पर यूनाइटेड किंगडम के विधि आयोग की रिपोर्टः न्यायालय को बदनाम करना (न्यायालय की अवमाननाः अदालत को बदनाम करना ", (2012) द लॉ कॉम नंः 335 [लंदन "(स्टेशनरी कार्यालय)]:

14 * (1974) I एस. सी. सी. 374-श्री बरदकांत मिश्रा बनाम। उड़ीसा उच्च न्यायालय के पंजीयक और एक अन्य;

(2002) 3 एस. सी. सी. 343:

अरुंधति रॉय की सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[201
7] 9 एस सी आर।

25. किसी भी न्यायिक कार्यवाही के नियत समय के साथ हस्तक्षेप है

आपराधिक अवमानना का एक और पहलू। अवमानक का आचरण

विभिन्न आदेश पारित करने के उद्देश्य से 2017 की स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका संख्या 1 की शुरुआत के बाद, जिसका विवरण निम्नलिखित में निहित है -

भारत के मुख्य न्यायाधीश के फैसले के पैराग्राफ 22 से 26 में इस सवाल के बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि क्या ऐसा आचरण दंडनीय होगा।

उच्चतम न्यायालय में लंबित न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना

के प्रारंभिक नोटिस द्वारा उनके खिलाफ लाया गया अवमानना आयोग न्यायालय दिनांकित 08.02.2017। इसके बजाय, उन्होंने एक कठिन चुनौती में शामिल होने का फैसला किया

उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ अवमानना के आरोप की जांच करने के लिए इस न्यायालय की अधिकारिता। उन्होंने कई लोगों को संबोधित किया था

मामले से निपटने वाली पीठ के सदस्यों को लिखित संचार और कई कथित न्यायिक आदेश भी पारित किए गए थे, जो सरसरी नज़र में भी अवमाननापूर्ण हैं। द.

" नोटिस के बाद के आचरण और अवमानकर्ता के कार्यों को अपेक्षा के न्यूनतम मानक से आंका जाना चाहिए, निश्चित रूप से, हमारे सामने क्या है

एक ऐसा न्यायाधीश है जिसने अपेक्षित और अनुमेय राय की अभिव्यक्ति के सबसे उदार मानकों को भी पार कर लिया है। हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि अवमानकर्ता की ओर से इस तरह के आचरण से उसकी बदनामी हुई है।

न्यायिक प्रणाली और विश्वास को हिलाने की क्षमता है

प्रणाली में औसत नागरिक। उन्होंने थोड़ा भी पछतावा नहीं दिखाया है।

जो एक शमन कारक हो सकता है। ऐसा आचरण और कार्रवाई, यदि बर्दाश्त की जाती है,

निश्चित रूप से प्रणाली में कमजोरी के एक तत्व को प्रतिबिंबित करेगा; ऐसा कोई नहीं है

कमजोरी को प्रणाली में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है।

विचाराधीनता के दौरान अवमानकर्ता का आचरण

इस न्यायालय में कार्यवाही निश्चित रूप से आपराधिक अवमानना का गठन करती है जो न्यायालय को बदनाम करने के साथ-साथ इस न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के दोनों शीर्षों के तहत आती है। हमारे विचार में, इसलिए अवमानकर्ता इस न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी

है। 26. हमारी राय में, इस मामले का महत्व तत्काल समस्या से परे है। यह मामला दो बातों पर प्रकाश डालता है, (1)

न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करें

संवैधानिक न्यायालय, उस मामले के लिए सभी स्तरों पर न्यायपालिका का कोई भी सदस्य; और (2) आई. एन. आर. ई., माननीय श्री न्याय सी. एस. कर्णन से निपटने के लिए उपयुक्त कानूनी व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता।

[चेलामेश्वर, जे।]

ऐसी स्थितियाँ जहाँ संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण की आवश्यकता होती है

सुधारात्मक उपाय-महाभियोग के अलावा-किए जाने चाहिए।

27. पीठ में उनकी पदोन्नति के बाद से अवमानक का आचरण विवादास्पद रहा है। जाहिर है, एक बनाने में विफलता है

के समय अवमानक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन

पदोन्नति के लिए उनके नाम की सिफारिश करना। हमारा उद्देश्य उंगली उठाना नहीं है।

उन व्यक्तियों के लिए जो सिफारिश के लिए जिम्मेदार थे लेकिन केवल

एक उपयुक्त प्रक्रिया प्रदान नहीं करने की प्रणाली की विफलता को उजागर करें

इस तरह का मूल्यांकन करने के लिए। कौन-सा उपयुक्त तंत्र होगा

उम्मीदवार के व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए उपयुक्त होना

संवैधानिक न्यायालय के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए माना जाने वाला एक ऐसा मामला है जिसकी पहचान सभी द्वारा उचित बहस के बाद की जानी चाहिए।

संबंधित-बार, बेंच, राज्य और सिविल सोसाइटी। लेकिन द.

आवश्यकता निर्विवाद प्रतीत होती है।

28. हमें केवल यह बताते हुए दुख हो रहा है कि शर्मिंदगी के अलावा

कि इस पूरे प्रकरण ने भारतीय न्यायपालिका को परेशान किया है, वहाँ हैं

विभिन्न अन्य उदाहरण (जो जनता के लिए कम ज्ञात हैं)

न्यायपालिका के कुछ सदस्यों का आचरण जो निश्चित रूप से

: इससे व्यवस्था को कुछ शर्मिंदगी होगी। 29. संविधान के निर्माता महान भावना वाले लोग थे

देशभक्ति और परिपक्वता के, पुरुष और महिलाएँ जिन्होंने उच्च बनाए रखा

नागरिक नैतिकता के मानक। जाहिर है, वे उन लोगों से उम्मीद करते थे जिन्हें उच्च संवैधानिक पदों के लिए चुना जाना है या जनता के लिए नियुक्त किया जाना है

सेवा को उनकी उपयुक्तता (दक्षता और क्षमता) का आकलन करके चुना जाएगा।

सत्यनिष्ठा) उचित मानकों को नियोजित करके। के निर्माताओं

संविधान इस तथ्य से अवगत था कि उच्च पदों पर आसीन होने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा ईमानदारी और पदधारी की गारंटी हो।

कोई भी संवैधानिक पद कार्यालय की प्रकृति और अपेक्षित आचरण के मानकों के साथ असंगत व्यवहार का सहारा ले सकता है। इसके बाद,

धारकों के महाभियोग के लिए संविधान में प्रावधान किए गए थे भारत के राष्ट्रपति से शुरू होने वाले विभिन्न संवैधानिक कार्यालय।

30. जब यह संवैधानिक न्यायालयों के सदस्यों के लिए समान रूप से आया, तो यह कल्पना की गई कि ऐसे अवसर हो सकते हैं। लेकिन द.

न्यायाधीशों के महाभियोग के लिए मानक और प्रक्रिया बहुत अधिक हैं।

स्पष्ट कारणों के लिए कठोर। आचरण में विचलन हो सकते हैं

} "

संवैधानिक न्यायालयों के पदों के धारक जो व्यक्ति के महाभियोग या ऐसे महाभियोग के लिए सभी हैं, निश्चित रूप से ऐसे मामलों से निपटने के अन्य तरीके होने चाहिए। संविधान इस संबंध में चुप है। हो सकता है कि यह समय हो

इस मुद्दे को सुलझाएँ।

अवमानना पेटीटी